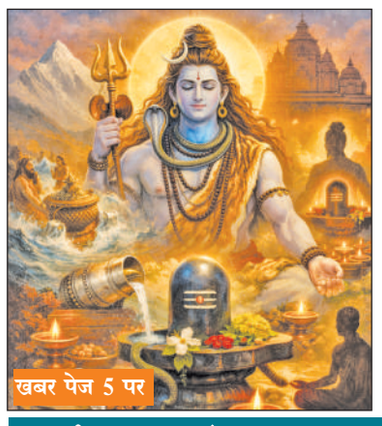
खबर पेज 5 पर

MOHTA Publishing House

गंभीर समाचार

समय–समाज–संस्कृति

खबर पेज 8 पर

वर्ष -12 | अंक–22 | पाक्षिक समाचार पत्रिका | कोलकाता, रविवार 1 – 15 फरवरी 2026 | मूल्यः 5 रुपये | RNI No.WBHIN/2014/59321, ISSN No. 2456/3005 Kolkata | कुल पृष्ठ – 8

सुविचार

- सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नही बल्कि मजबूत बनाने आती है।
- कान भरने वाले लोग किसी से उलझते नहीं है वस आग लगाकर अलग हो जाते है।

शेरो-शायरी

- हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो।
- मोहब्बत के अगर 100 हिस्से किये जाए तो 99 हिस्सों की हकदार हमारी मां है।
- कभी ठंडी बर्फ सा पिघल जाता हूं, कभी रेत की तरह फिसल जाता हूं, कभी दिल खोल कर रख देता हूं किसी के सामने, कभी बिना कुछ बोले चुपचाप निकल जाता हूं।

'डेस्टिनेशन वेडिंग' के लिए सजाए जाएंगे 20 सरकारी रिसॉर्ट्स

कंचनजंगा की हसीन वादियों में जोड़े लेंगे शादी के फेरे

निज संवाददाता : क्या हो अगर पहाड़ की गोद में कंचनजंगा को साक्षी मानकर शुभ की कामना की जाए? जंगल के हरे-भरे कालीन पर वरमाला पहनाई जाए? या रेत में शादी की जाए? बहुत से लोग अपनी पसंद की जगह पर अपने प्रियजनों के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। लेकिन उनकी जेब इसकी इजाज़त नहीं देती। किसी प्राइवेट रिसॉर्ट या होटल में शादी करना बहुत महंगा होता है। यह मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर है। अब उनकी इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता बन गया है। बादलों के राज में, किसी समुद्री शहर में या घने जंगल में किसी सरकारी रिसॉर्ट में बहुत कम खर्च में शादी समारोह करने का सुनहरा मौका बन रहा है। जिसे बजट-फ्रेंडली डेस्टिनेशन वेडिंग कहा जाता है। हालांकि सरकार के पास शादियों के लिए 40 रिसॉर्ट और होटल हैं जिन्हें डेवलप किया जा सकता है, वेस्ट बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन शुरुआती स्टेज में 20 के साथ आगे बढ़ना चाहता है। राज्य टूरिज्म डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव वरुण रॉय ने बताया कि इस साल पूजा के बाद पहले फेज में कम से कम दस ऐसे रिसॉर्ट शुरू करने का प्लान है। अभी सर्वे शुरू किया गया है। यह दो महीने में पूरा हो जाएगा। फिर रिसॉर्ट्स को सजाने का काम शुरू होगा। वरुण के मुताबिक, टूरिस्ट सेंटर्स में शादियां करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास

जरूरी है। इसके लिए मॉडर्न बैंक्वेट हॉल, नए शादीशुदा जोड़ों के लिए स्पेशल हनीमून सुइट्स और रेनोवेट किए गए लग्जरी घरों का इंतजाम किया जा रहा है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कर्सियांग जैसे पहाड़ी इलाकों से लेकर दीघा के बीच, झाड़ग्राम के जंगल या पुरुलिया के ऊबड़-खाबड़ इलाकों तक, इस टूरिज्म पैकेज के लिए बहुत संभावना है। चूंकि लोग अपनी शादियों की प्लानिंग बहुत पहले से करते हैं, इसलिए सरकार कुछ ही दिनों में संभावित रिसॉर्ट्स की लिस्ट जारी करेगी। बुकिंग लेने का काम शुरू होगा। तभी राज्य को परीकथाओं की शादी का फायदा मिलेगा।अनंत अंबानी की परीकथाओं की शादी की चर्चा देश की सीमाओं से बाहर विदेशों में भी हो रही है। सिल्वर स्क्रीन पर ऐसी परीकथा जैसी डेस्टिनेशन वेडिंग अब होने लगी हैं। लेकिन प्राइवेट रिसॉर्ट्स की आसमान छूती कीमतों ने उस सपने को दबा दिया है। यह सपना अब सरकार की पहल पर जंगल का रूप लेगा। कभी चीड़ के पेड़ों की जुगलबंदी में, तो कभी लहरों की लय में। हाल ही में पार्क होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में सचिव ने कई टूरिज्म पार्टनर्स के साथ इस संभावना को साझा किया। विभाग का लक्ष्य है कि अगले विंटर वेडिंग सीजन (सर्दियों का शादी का मौसम) से इस सर्विस को शुरू करने की कोशिश की जाए। शादियों के साथ-साथ राज्य में एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। ट्राइबल टूरिज्म की शुरुआत हाइकिंग, हॉट एयर बैलून राइड या ट्रेकिंग जैसी कम जोखिम वाली एक्टिविटीज से होगी।

मेयर फिरहाद हकीम ने पेश किया कोलकाता नगर निगम का बजट

निज संवाददाता : कोलकाता नगर निगम हेडक्वार्टर में मेयर फिरहाद हकीम ने अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया। हालांकि यह पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम था, लेकिन नगर निगम अधिकारियों को घाटे के साथ बजट पेश करना पड़ा। नगर निगम की जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-2026 में बजट घाटा 122.06 करोड़ रुपये था। इस साल यह घाटा घटकर 111 करोड़ रह गया है। हालांकि, नगर निगम तय इनकम टारगेट तक नहीं पहुंच सका। यह भी पता चला है कि पीने के पानी समेत कई एरिया में एलोकेशन तो किया गया था, लेकिन उसे पूरी तरह खर्च नहीं किया जा सका। हालांकि, पानी, सड़क और बिजली जैसे आधारभूत संरचना के मुद्दों के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। कोलकाता नगर निगम के एक धड़े का दावा है कि कोलकाता नगर निगम के चुनाव इस साल विधानसभा चुनाव के बाद दिसंबर में होंगे। मेयर वोटिंग से पहले आखिरी बजट में कोई खास रिस्क नहीं लेना चाहते थे।हालांकि, बजट पेश होने के बाद विपक्ष की तरफ से तीखी आलोचना शुरू हो गई। विपक्षी पार्षदों ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार के लक्ष्मी भंडार और बंगाल आवास योजना प्रोजेक्ट्स का ज़िक्र नगर निगम के बजट में क्यों किया गया। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार के सोशल प्रोजेक्ट्स को नगर निगम के बजट में घसीटना गलत है और यह फाइनेंशियल तस्वीर छिपाने की कोशिश है।

बंगाल कोयला घोटाले से जुड़ी कंपनियों की जब्त की 100.44 करोड़ की संपत्ति

ईडी की बड़ी कार्रवाई

निज संवाददाता : गैरकानूनी कोयला खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100.44 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर दी है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत की गई है। मामला ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के लीज एरिया में बड़े पैमाने पर अवैध खनन और कोयला चोरी से जुड़ा है। जांच में सामने आया है कि इस पूरे रैकेट को अनूप मांझी उर्फ लाला के नेतृत्व में एक सिंडिकेट चला रहा था। आरोप है कि सिंडिकेट ने बड़े पैमाने पर अवैध खुदाई कर कोयला निकाला और फिर उसे पश्चिम बंगाल की कई फैक्ट्रियों तक पहुंचाया। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस काम में स्थानीय प्रशासन की सक्रिय मदद ली जा रही थी।

ईडी की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सिंडिकेट ने एक फर्जी ट्रांसपोर्ट चालान शुरू किया था, जिसे 'लाला पैड' कहा जाता था। यह चालान गैर-मौजूद कंपनियों के नाम पर टैक्स इनवॉइस की तरह जारी किया जाता था। ट्रक ड्राइवरों को फर्जी चालान के साथ 10 या 20 रुपये का एक नोट भी दिया जाता था। ड्राइवर उस नोट को ट्रक या डंपर के नंबर प्लेट के साथ पकड़कर उसकी फोटो खींचता और सिंडिकेट ऑपरेटर को भेजता था। इसके बाद वही फोटो व्हाट्सएप के जरिए रास्ते में पड़ने वाले पुलिस और दूसरे अधिकारियों तक पहुंचाई जाती थी, ताकि गाड़ी को रोका न जाए या रोके जाने पर तुरंत छोड़ दिया जाए।

2,742 करोड़ की कमाई का अंदेशा :

ईडी के मुताबिक, सिंडिकेट के रिकॉर्ड में करीब 2,742 करोड़ रुपये की अवैध कमाई दर्ज मिली है। जब्त रजिस्टर, डिजिटल डेटा, टैली रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि बड़े पैमाने पर कैश ट्रांजैक्शन और हवाला के जरिए पैसे को इधर-उधर किया गया। जांच में एक अंडरग्राउंड हवाला नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। लेन-देन के लिए एक खास कोड इस्तेमाल किया जाता था, जो आमतौर पर 10 रुपये के नोट का सीरियल नंबर होता था। पैसे लेने वाला पहले नोट का सीरियल नंबर भेजता था। फिर वही नंबर हवाला ऑपरेटर के जरिए दूसरे शहर में मौजूद व्यक्ति को दिया जाता था। जब कैश पहुंचाया जाता, तो रिसीवर वही खास नंबर वाला नोट दिखाकर अपनी पहचान साबित करता और बिना किसी बैंक रिकॉर्ड के कैश ले लेता। इस तरह करोड़ों रुपये बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के इधर-उधर किए गए।

ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि स्टील और आयरन सेक्टर की कुछ कंपनियों ने नकद में अवैध कोयला खरीदा। इससे उन्होंने अवैध कमाई को साफ दिखाने में मदद की। अटैच की गई संपत्तियों में जमीन-जायदाद, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड निवेश शामिल हैं। ये संपत्तियां शाकंभरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड और गगन फेरोटेक लिमिटेड के नाम पर हैं। इस मामले में अब तक कुल 322.71 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।

इससे पहले 8 जनवरी 2026 को ईडी ने कोलकाता और दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन छापों में मिले सबूतों के आधार पर अब इन संपत्तियों को अटैच किया गया है।

ईडी का कहना है कि यह पूरा मामला कई परतों वाला और जटिल आर्थिक अपराध है। एजेंसी अब इस नेटवर्क के अंतिम लाभार्थियों और अन्य शामिल लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ईडी ने साफ किया है कि अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध देश के प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं और जनता के हितों के खिलाफ हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बांग्लादेश में बीएनपी की भारी जीत

भारत के लिए क्या हैं सियासी मायने?

निज संवाददाता : बांग्लादेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने फरवरी 2026 के संसदीय चुनावों में भारी जीत हासिल की है। उसने 300 सीटों में से 151 से 209 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। इससे बंगलादेश में बीएनपी की भारी जीत से भारत के लिए सियासी निहितार्थ स्पष्ट हैं, क्योंकि यह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग के पतन के बाद पहला बड़ा चुनाव है, जो 2024 के छात्र-आंदोलन से उभरा था। चूंकि बीएनपी पहले से सत्ता में रहती आई है, इसलिए उसकी जीत के वैश्विक मायने भी हैं। वह यह कि पार्टी कमोबेश पूर्व प्रधानमंत्री स्व.बेगम खालिदा जिया के अधूरे सपनों को ही साकार करेगी। वो भी तब जब उनके पुत्र तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। देखा जाए तो बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी को काफी पीछे छोड़ते हुए प्रचंड जीत दर्ज की है, जहां जमात को महज 42-68 सीटें ही मिलीं हैं। बीएनपी की जीत की वजह यह है कि पार्टी ने गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार विरोध और विदेशी निवेश पर जोर दिया है। इससे भारत के लिए सियासी मायने भी साफ हैं। भले ही भारत-बीएनपी संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर पाकिस्तान और जमात से बीएनपी के पुराने गठजोड़ के कारण। इसलिए उनकी जीत से भारत को सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता और चरमपंथी समूहों की चिंता बढ़ सकती है, हालांकि बीएनपी समानता-आधारित संबंधों का वादा कर रही है। खासकर हसीना युग के बाद विदेश नीति में बदलाव से व्यापार, जल बंटवारा और कनेक्टिविटी पर असर पड़ सकता है।वहीं बीएनपी की जीत से दुनिया के लिए भी सियासी मायने साफ हैं। बीएनपी की जीत बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता ला सकती है, लेकिन विदेश नीति में संतुलन अपनाने से चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। वहीं दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक बदलाव संभव है, जहां भारत के प्रभाव में कमी और चीन के निवेश (2.1 बिलियन) बढ़ सकता है। वैश्विक रूप से, यह क्षेत्रीय गठबंधनों को प्रभावित कर सकता है, खासकर म्यांमार शरणार्थी और आर्थिक सुधारों के संदर्भ में।यह

ठीक है कि भारत और बीएनपी के बीच संबंध सुधारने के प्रयास चुनाव से पहले ही शुरू हो चुके हैं, जिसमें एस जयशंकर की तारिक रहमान से ''बहुत मैत्रीपूर्ण'' चर्चा शामिल है। हालांकि हसीना के भारत में रहने से तनाव बरकरार है, फिर भी दोनों पक्ष सहयोग बढ़ाने को इच्छुक दिख रहे हैं। इसलिए संभावित सुधार के कदम उठाये जा सकते हैं। खासकर राजनयिक संपर्क बढ़ाना, क्योंकि भारत ने बीएनपी नेताओं से मुलाकातें कीं, जैसे प्रणय वर्मा की मीरजा फखरुल से, जहां बीएनपी ने भारत की सुरक्षा हितों का सम्मान करने का आश्वासन दिया। वहीं, व्यापार और वीजा बहाली के दृष्टिगत यात्रा, व्यापार और वीजा प्रतिबंध हटाने पर फोकस किया जा सकता है, जो हसीना के बाद बाधित हो गए थे। खासकर जल बंटवारा और सीमा मुद्दे हल करना यानी बीएनपी पानी बंटवारे और सीमा हत्याओं (जैसे फेलानी घटना) पर जोर दे रही है। इसलिए कुछ चुनौतियां भी आएंगी, क्योंकि बीएनपी हसीना की प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, जिसे भारत शरण दे रहा है, इससे जन-भावना भी प्रभावित हो रही है। वहीं,जमात-ए-इस्लामी का प्रभाव और पाक-चीन झुकाव भारत की चिंता बढ़ा सकता है। फिर भी भविष्य की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। चूंकि बीएनपी ''समानता-आधारित'' पड़ोसी संबंधों का वादा कर रही है, जबकि भारत अल्पसंख्यक सुरक्षा और चरमपंथ विरोध की शर्त रख रहा है। इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार, व्यावहारिक आवश्यकताएं रीसेट सुनिश्चित करेंगी, लेकिन ऐतिहासिक अविश्वास दूर करने में समय लगेगा। हालांकि, तारिक रहमान, जो बीएनपी के प्रमुख नेता हैं, और भारत के प्रति संयमित और तटस्थ रुख अपनाते दिख रहे हैं, जो अतीत के तनावपूर्ण रिश्तों से अलग है। वे समानता-आधारित पड़ोसी संबंधों पर जोर देते हैं, लेकिन शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखते हैं। उनका मुख्य स्टैंडपॉइंट्स यह है कि अल्पसंख्यक सुरक्षा और स्थिरता के नजरिए से वो अपने भाषणों में अहिंसा, कानून के राज और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया, जो भारत की चिंताओं को संबोधित करता है। वहीं, समानता का जोर के मद्देनजर ''बराबरी के रिश्ते'' चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पुरानी असमानताओं (जैसे जल बंटवारा, सीमा हत्याएं) पर बात उठाई, लेकिन टकराव से बचते हैं। हां, भारत में शरण लेने वाली हसीना को वापस लाने की मांग,जो सबसे बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। हालांकि हालिया संकेत यही है कि ढाका लौटने के बाद उनके संयमित भाषण को खुफिया एजेंसियां ''इंडिया-न्यूट्रल'' मान रही हैं, जो 2001-06 के भारत-विरोधी दौर से अलग है। लिहाजा भारत के साथ सहयोग संभव, लेकिन पाकिस्तान-चीन झुकाव और जमात प्रभाव चिंता का विषय है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि व्यावहारिकता से रिश्ते सुधर सकते हैं। देखा जाए तो तारिक रहमान के हालिया भाषणों में भारत का सीधा जिक्र बहुत कम या न के बराबर आया है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। वहीं उनके भाषणों की मुख्य शैली में भारत का प्रत्यक्ष उल्लेख न करना समाहित है। खासकर ढाका लौटने (25 दिसंबर 2025) के 17 मिनट के पहले भाषण में भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन अल्पसंख्यक सुरक्षा (हिंदू, बौद्ध आदि), अहिंसा और कानून के राज पर जोर दियाजो भारत की प्रमुख चिंताओं को संबोधित करता है।

एयरपोर्ट पर किफायती होगा खान-पान

कोलकाता समेत देश के हर हवाईअड्डे पर खुलेगा 'उड़ान यात्रा कैफे'

निज संवाददाता : अब एयरपोर्ट पर किफायती दर पर खान-पान मिलेगा। यानी हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर महंगे चाय-नाश्ते से राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने देश के सभी एयरपोर्ट पर सस्ते दामों में खान-उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि साल के अंत तक हर एयरपोर्ट पर 'उड़ान यात्रा कैफे' खोलने का लक्ष्य तय किया गया है। फिलहाल देश के चुनिंदा एयरपोर्ट पर यह सुविधा उपलब्ध है। इनमें कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर और चेन्नई एयरपोर्ट शामिल हैं। दरअसल, देश के एयरपोर्ट पर महंगे दामों में चाय-सैंडविच वगैरह मिलते हैं। कुछ जगहों पर तो चाय के दाम 200 से 300 रुपये तक है। आवाज उठाई गई थी लोगों को सस्ते दामों पर खान-पान की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्रा कैफ़े खोलने का फैसला किया था। इसकी शुरुआत पिछले साल जनवरी 2025 में कोलकाता एयरपोर्ट से की गई थी। वहां यात्री दस रुपये में चाय, बीस रुपये में कॉफी, दस रुपये में पानी की बोतल, बीस रुपए में समोसा और इतने ही रुपये में रसगुल्ला ले सकता है। बताया जा रहा है कि पुणे एयरपोर्ट पर खोले गए कैफे की खास बात यह है कि इसमें महिला कर्मचारियों को ही रखा गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने बताया कि सरकार का उद्देश्य यात्रियों को एयरपोर्ट पर गुणवत्तापूर्ण और किफायती खान-पान सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि खाने की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और किसी भी शिकायत की स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने कहा कि उड़ान यात्रा कैफे में 5 आइटम रखे गए हैं। इनमें चाय, कॉफी, पानी और समोसे के साथ एक स्थानीय व्यंजन को भी जगह दी गई है। जैसे कोलकाता में रसगुल्ला या पुणे में वड़ा पाव मिल रहा है। मंत्रालय के अनुसार इन कैफे को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। लोगों को यहां के चाय-समोसे खूब पसंद आ रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि इस साल के अंत तक हर एयरपोर्ट पर एक ऐसा कैफे खोला जाए। हालांकि यह तय किया गया है कि एक एयरपोर्ट पर एक ही कैफे खोला जाएगा। इस पर का शुरू कर दिया जाएगा। साल के अंत तक सभी एयरपोर्ट पर कैफे शुरू किए जा सकते हैं।

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कोलकाता के दो विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता ज्यादा

अध्ययन रिपोर्ट में हुआ खुलासा

निज संवाददाता : चुनाव आयोग के मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के एक अध्ययन में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पाया गया है कि दक्षिण कोलकाता के दो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में जिन मतदाताओं में विसंगति पाई गई, उनमें मुस्लिम श्रेणी के मतदाता सबसे ज्यादा थे। यह अध्ययन सबार इंस्टीट्यूट ने किया है। शोध के अनुसार, शहर के पारंपरिक वाणिज्यिक और राजनीतिक केंद्र के आसपास स्थित मध्य-दक्षिण कोलकाता के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में तार्किक विसंगति के अंतर्गत चिह्नित मतदाताओं में से लगभग 52 फीसदी मुस्लिम हैं और दक्षिण कोलकाता के एक समीपवर्ती पॉश आवासीय क्षेत्र बालीगंज में यह संख्या लगभग 78 फीसदी है। अध्ययन से पता चलता है कि भवानीपुर में, 15,145 मतदाताओं में से 7,846 मुस्लिम हैं, जिनके जनगणना प्रपत्रों में तार्किक विसंगतियां के कारण निशान लगाए गए थे। बालीगंज में, इसी श्रेणी के 30,008 मतदाताओं में से 23,256 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। अन्य श्रेणियों में हटाए गए या संशोधित किए गए मतदाताओं की तुलना में यह असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अध्ययन करने वाले आशिन चक्रवर्ती ने सौप्तिक हल्दर और साबिर अहमद के साथ मिलकर यह अध्ययन किया। आशिन ने कहा कि भवानीपुर में, अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत/डुप्लिकेट (एएसडी) के रूप में चिह्नित मतदाताओं में मुस्लिम केवल 22.7 फीसदी हैं और बिना मानचित्रित मतदाताओं में लगभग 26 फीसदी हैं। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम आबादी के लगभग 20 फीसदी हिस्से से काफी हद तक मेल खाते हैं। लेकिन तार्किक विसंगति के तहत, यह अनुपात तेजी से बढ़कर 52 फीसदी हो जाता है। बालीगंज में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है, जहां एएसडी मतदाताओं में मुसलमानों की संख्या लगभग 44 फीसदी और अनमैप्ड मतदाताओं में 42 फीसदी है, जो निर्वाचन क्षेत्र में उनकी अनुमानित 50 फीसदी जनसंख्या हिस्सेदारी के करीब है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पक्षपात के आरोपों को खारिज कर दिया।

एक चुनाव आयोग अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में धर्म का रिकॉर्ड नहीं होता और आयोग धर्मवार मतदाता डेटा नहीं रखता है। राजनीतिक विश्लेषक उदयन बंद्योपाध्याय ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) के लिए इस्तेमाल किया गया एआई प्रोग्राम अल्पसंख्यक मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं को परेशान करने के लिए जानबूझकर बनाया गया था। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने भाजपा पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए मतदाता सूची संशोधन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इन निष्कर्षों ने कोलकाता में एसआईआर प्रक्रिया में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और सॉफ्टवेयर-आधारित तार्किक विसंगति फ़िल्टर की ऑडिट की मांग बढ़ रही है। मांग की जा रही है कि ऑडिट किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संशोधन प्रक्रिया किसी भी समुदाय को असमान रूप से प्रभावित न करे। बंगाल भाजपा प्रमुख सामिक भट्टाचार्य ने इस आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि इस मुद्दे का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है और आरोप लगाया कि अवैध प्रवासियों को मतदाता के रूप में नामांकित किया गया है।

धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण त्यौहार है महाशिवरात्रि

रमेश सर्राफ धमोरा

भगवान शिव का त्यौहार है महाशिवरात्रि। भारत के सभी प्रदेशो में महाशिव रात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के साथ नेपाल, मारिशस सहित दुनिया के कई अन्य देशों में भी महाशिवरात्रि मनाते है। हर साल फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिव रात्रि का व्रत किया जाता है। हिन्दू पुराणों के अनुसार इसी दिन सृष्टि के आरंभ में मध्यरात्रि मे भगवान शिव ब्रह्मा से रुद्र के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है।योगिक परम्परा में इस दिन और रात को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह आध्यात्मिक साधक के लिए जबर्दस्त संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक विज्ञान कई चरणों से गुजरने के बाद आज उस बिंदु पर पहुंच गया है। जहां वह प्रमाणित करता है कि हर वह चीज जिसे आप जीवन के रूप में जानते हैं। पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं। जिसे आप ब्रह्मांड और आकाशगंगाओं के रूप में जानते हैं। वह सिर्फ एक ही ऊर्जा है। जो लाखों रूपों में खुद को अभिव्यक्त करती है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है। इस दिन सभी शिव मंदिरों में भीड़-भाड़ का माहौल रहता है। महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्त महादेव की कृपा पाने के लिए विधिवत पूजा-पाठ करते हैं। पंचांग के अनुसार शिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है।महाशिवरात्रि आध्यात्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। इस रात धरती के उत्तरी गोलार्ध की स्थिति ऐसी होती है कि इंसान के शरीर में ऊर्जा कुदरती रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। इस दिन प्रकृति इंसान को अपने आध्यात्मिक चरम पर पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग महाशिवरात्रि को शिव की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाएं रखने वाले लोग इस दिन को शिव की दुश्मनों पर विजय के रूप में देखते हैं।

माना जाता है की इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते है। महाशिवरात्रि का व्रत रखना सबसे आसान माना जाता है। इसलिये बच्चों से लेकर बूढ़ो तक सभी इस दिन व्रत रखते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत रखने वालों के लिये अन्न खाना मना होता है। इसलिये उस दिन फलाहार किया जाता है। राजस्थान में व्रत के समय गाजर, बेर का सीजन होने से गांवों में लोगों द्वारा गाजर, बेर का फलाहार किया जाता है। लोग मन्दिरों में भगवान शिव की पूजा करते हैं व उन्हे आक, धतूरा चढ़ाते हैं। भगवान शिव को विशेष रूप से भांग का प्रसाद लगता है। इस कारण इस दिन काफी जगह शिवभक्त भांग घोट कर पीते हैं। पुराणों में कहा जाता है कि एक समय शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे थी। उसी समय पार्वती ने प्रश्न किया कि इस तरह का कोई व्रत है जिसके करने से मनुष्य आपके धाम को प्राप्त कर सके? तब उन्होंने यह कथा सुनाई थी कि प्रत्यना नामक देश में एक व्यक्ति रहता था, जो जीवों को बेचकर अपना भरण पोषण करता था। उसने सेठ से धन उधार ले रखा था। समय पर कर्ज न चुकाने के कारण सेठ ने उसको शिवमठ में बन्द कर दिया। संयोग से उस दिन फाल्गुन बदी चतुर्दशी थी। वहां रातभर कथा, पूजा होती रही जिसे उसने भी सुना। अगले दिन शीघ्र कर्ज चुकाने की शर्त पर उसे छोड़ा गया। उसने सोचा रात को नदी के किनारे बैठना चाहिये। वहां जरूर कोई न कोई जानवर पानी पीने आयेगा।

अतः उसने पास के बील वृक्ष पर बैठने का स्थान बना लिया। उस बील के नीचे एक शिवलिंग था। जब वह पेड़ पर अपने छिपने का स्थान बना रहा था उस समय बील के पत्तों को तोडकर फेंकता जाता था जो शिवलिंग पर ही गिरते थे। वह दो दिन का भूखा था। इस तरह से वह अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर ही चुका था। साथ ही शिवलिंग पर बेल-पत्र भी अपने आप चढ़ते गये।

एक पहर रात्रि बीतने पर एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई। उस व्याध ने तीर को धनुष पर चढ़ाया किन्तु हिरणी की कातर वाणी सुनकर उसे इस शर्त पर जाने दिया कि सुबह होने पर वह स्वयं आयेगी। दूसरे पहर में दूसरी हिरणी आई। उसे भी छोड़ दिया। तीसरे पहर भी एक हिरणी आई उसे भी उसने छोड़ दिया और सभी ने यही कहा कि सुबह होने पर मैं आपके पास आऊंगी। चौथे पहर एक हिरण आया। उसने अपनी सारी कथा कह सुनाई कि वे तीनों हिरणियां मेरी स्त्री थी। वे सभी मुझसे मिलने को छटपटा रही थी। इस पर उसको भी छोड़ दिया तथा कुछ और भी बेल-पत्र नीचे गिराये। इससे उसका हृदय बिल्कुल पवित्र, निर्मल तथा कोमल हो गया।प्रातः होने पर वह बेल-पत्र से नीचे उतरा। नीचे उतरने से और भी बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ गये। अतः शिवजी ने प्रसन्न होकर उसके हृदय को इतना कोमल बना दिया कि अपने पुराने पापों को याद करके वह पछताने लगा और जानवरों का वध करने से उसे घृणा हो गई। सुबह वे सभी हिरणियां और हिरण आये। उनके सत्य वचन पालन करने को देखकर उसका हृदय दुध सा धवल हो गया और वह फूट-फूट कर रोने लगा।

महाशिवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में ईश्वरीय शक्ति के महत्व को दिखलाता है। हमें भगवान शिव के द्वारा मानव जाति तथा सृष्टि के कल्याण के लिए विषपान जैसे असीम त्याग को प्रदर्शित करता है। यह दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो ईश्वर भी हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। लोगों का मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव हमारे निकट होते हैं और इस दिन पूजा अर्चना तथा रात्रि जागरण करने वालों को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। कई लोग इस दिन दान धर्म करते है तथा गरीबों को खाना खिलाकर भगवान शिवजी से अपनी सुखी जीवन के लिए प्राथना करते है।शिवरात्रि के प्रसंग को हमारे वेद, पुराणों में बताया गया है कि जब समुद्र मन्थन हो रहा था उस समय समुद्र में चौदह रत्न प्राप्त हुए। उन रत्नों में हलाहल भी था।

स्वास्थ्यसाथी के तहत अब प्राइवेट अस्पतालों में भी हो सकेंगी चार प्रमुख सर्जरी

- सूची में हर्निया, हाइड्रोसील, फ्लेबेक्टोमी और आर्थोस्कोपिक
- स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया दिशा-निर्देश

निज संवाददाता : बंगाल के पिछड़े तबके के लोगों के लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्यसाथी स्कीम के तहत अब प्राइवेट अस्पतालों में हर्निया, हाइड्रोसील, फ्लेबेक्टोमी और आर्थोस्कोपिक सर्जरी हो सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में नई गाइडलाइंस (दिशा-निर्देश) जारी की हैं। राज्य में स्वास्थ्यसाथी स्कीम शुरू होने के बाद ये चार सर्जरी प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हो पा रही थीं। स्वास्थ्य विभाग का तर्क था कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर (आधारभूत संरचना) में इन सभी सर्जरी के लिए एडवांस सुविधाएं हैं। लेकिन अब ये चार सर्जरी प्राइवेट अस्पतालों में भी स्वास्थ्यसाथी कार्ड का इस्तेमाल करके हो सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अगर सरकारी अस्पताल में हर्निया, हाइड्रोसील, फ्लेबेक्टोमी सर्जरी करने में कोई दिक्कत आती है और संबंधित डॉक्टर उसे लिखते हैं, तो ही प्राइवेट अस्पताल में वही सर्जरी हो सकेगी। अगर किसी एक्सीडेंट में घायल मरीज को आर्थोस्कोपिक सर्जरी की जरूरत होती है, तो ही स्वास्थ्यसाथी स्कीम के तहत प्राइवेट अस्पताल में वही हो सकेगी। लेकिन कोल्ड-ओटी, यानी बाद में होने वाली सर्जरी के मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल में आर्थोस्कोपी नहीं हो सकती। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक-आम आदमी के फायदे के लिए इस गेटकीपिंग सिस्टम में ढील दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक, लंबे समय से देखने पर पता चला है कि उन चार मामलों में, सरकारी हॉस्पिटल में सर्जरी की डेट मिलने के लिए मरीजों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। कुछ मामलों में तो डेट भी नहीं मिलती, लेकिन मरीज को इंतजार करना पड़ता है। दूसरी ओर, स्वास्थ्य विभाग के ध्यान में एक और बात आई है कि सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों का एक ग्रुप जानबूझकर उन सर्जरी के लिए मरीजों को अलग-अलग वजहें बताकर प्राइवेट हॉस्पिटल भेज रहा है। वहां, वे डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं। हालांकि, गेटकीपिंग गाइडलाइंस में थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने यह साफ कर दिया है कि कौन से डॉक्टर वे सर्जरी कर सकते हैं। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अपने सर्जन ही वे सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन उस हॉस्पिटल से जुड़ा कोई भी सरकारी डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता।

'युवा साथी' के साथ ही कर सकेंगे 'लक्ष्मी भंडार' का भी आवेदन

निज संवाददाता : युवा साथी स्कीम के साथ लक्ष्मी भंडार के लिए नया एप्लीकेशन भी किया जा सकता है। नए आवेदक विधानसभा आधारित इलाके में लगने वाले कैंप में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। राज्य सरकार रविवार से राज्य के हर विधानसभा इलाके में कैंप लगाने जा रही है।सरकारी छुट्टियों को छोड़कर, 15 फरवरी से 26 फरवरी तक हर दिन राज्य के हर विधानसभा इलाके में कैंप लगेगा। वहां युवा साथी, खेतिहर मजदूरों को 4,000 रुपये सालाना मदद और किसानों द्वारा सिंचाई के पानी के इस्तेमाल के लिए तय पानी के टैक्स में छूट के लिए आवेदन जमा किए जाएंगे। इसकी घोषणा पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की थी। अब पता चला है कि लक्ष्मी भंडार के लिए नए एप्लीकेशन भी लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस बारे में अलग-अलग अखबारों में विज्ञापन दिए हैं। अब राज्य में करीब 2.42 करोड़ महिलाएं लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत वित्तीय मदद पा रही हैं।

जीजेएम प्रमुख बिमल गुरुंग का फूटा गुस्सा

अपनी 'हालत' के लिए बड़ी पार्टियों को ज़िम्मेदार ठहराया

निज संवाददाता : कभी दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र में किसी की दशा-दिशा और राजनीतिक किस्मत तय करने वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के नेता बिमल गुरुंग इन दिनों गुस्से में लग रहे हैं। हाशिए पर डाल दिए जाने और अपनी इस ''हालत'' के लिए लिए उन्होंने परोक्ष रूप से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ज़िम्मेदार ठहराया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी या तृणमूल को सपोर्ट करेंगे, तो गुरुंग, जिनका मोर्चा अभी बीजेपी के साथ अलायंस में है, ने कहा कि कोई फैसला नहीं हुआ है। गुरुंग ने कहा-हम लोगों का अभी फैसला नहीं हुआ है। टीएमसी, बीजेपी, हम लोगों ने सब को देखा है ना, सब पार्टी को देखा है और हमारा हालात ऐसा बनाया ना.... (हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। हमने टीएमसी और बीजेपी दोनों को देख लिया है और हम इस हालत में आ गए हैं)। बता दें कि 2007 से 2017 तक दार्जिलिंग पर गुरुंग का पूरा कंट्रोल था। 2009 के लोकसभा चुनावों में, उनकी पार्टी ने अकेले दम पर दार्जिलिंग से बीजेपी कैंडिडेट जसवंत सिंह की जीत पक्की की थी। हालांकि, 2011 के बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान लेफ्ट फ्रंट को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने तृणमूल की तरफ रुख

किया। बिमल की पार्टी और तृणमूल 2012 में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) पर सहमत हुए थे और उन्होंने एक बार तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ''हमारी मां'' कहा था। हालांकि, गुरुंग के ममता के साथ रिश्ते कभी अच्छे तो कभी बुरे होते रहे। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी नेता एस.एस. अहलूवालिया का समर्थन किया और उनकी जीत पक्की की। 2017 के गोरखालैंड आंदोलन के दौरान, तृणमूल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने आंदोलन को सख्ती से कुचल दिया और गुरुंग अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन उनका दबदबा इतना था कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी सांसद राजू बिस्टा की जीत पक्की की। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले, गुरुंग अंडरग्राउंड से बाहर निकलकर तृणमूल का समर्थन करने लगे और खुले तौर पर बीजेपी की आलोचना की। एक जानकार ने कहा-जिस पल उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल का समर्थन करने का फैसला किया, गुरुंग ने रातों-रात अपना पॉपुलर सपोर्ट खो दिया। तब से, गुरुंग अपनी खोई हुई ज़मीन वापस नहीं पा सके और उनकी पार्टी बाद के चुनाव नहीं जीत सकी। वह चाहे जीटीए हो या पंचायतें। पर्यवेक्षक ने आगे कहा-कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने अपनी किस्मत तृणमूल और बीजेपी के हाथों में होने की बात की। सूत्रों ने कहा कि गुरुंग चाहते हैं कि बीजेपी 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान तीन पहाड़ी सीटों में से कम से कम एक पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करे, लेकिन बीजेपी ने उनसे कोई वादा नहीं किया है। एक सूत्र ने कहा-बीजेपी ने पहाड़ियों में तेज़ी से अपनी जगह बनाई है और अब वह पहले की तरह उन पर निर्भर नहीं है। इसके अलावा, सितंबर 2021 में बनी और अनित थापा की लीडरशिप वाली भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा अब जीटीए को कंट्रोल करती है। भारतीय गोरखा जनशक्ति फ्रंट के नेता अजय एडवर्ड्स विपक्ष की एक अहम आवाज़ हैं।

एसआईआर की वजह से डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स के लिए मची होड़

9 दिसंबर से अब तक जारी किए गए 16,900 से ज़्यादा सर्टिफिकेट

निज संवाददाता : कोलकाता कलेक्ट्रेट ने बीते साल 9 दिसंबर से अब तक एसआईआर हियरिंग के दौरान जमा करने के लिए 16,900 से ज़्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए हैं। ऑफिस के सूत्रों ने बताया कि दिसंबर के आखिर में एसआईआर हियरिंग के नोटिस जारी होने से पहले, कलेक्ट्रेट हर साल लगभग 1,500 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करता था। अचानक आई तेज़ी इस बात को दिखाती है कि लोगों में ऐसे डॉक्यूमेंट्स पाने की होड़ मची हुई है जिनसे यह पक्का हो सके कि उनका नाम वोटर लिस्ट से न हटाया जाए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट (स्थायी निवास प्रमाण पत्र) भी कहा जाता है, उन एप्लीकेंट्स को जारी किया जाता है जो किसी जगह पर कम से कम 15 साल से रह रहे हों। ऐसे सर्टिफिकेट कई कामों के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनमें प्रतियोगी परीक्षा के लिए एप्लीकेशन, जहां स्टेट डोमिसाइल (राज्य निवास) के लिए सीटें रिज़र्व होती हैं, दूसरे राज्यों में हॉस्टल एप्लीकेशन, डिफेंस से जुड़ी नौकरियां और ऑर्गन ट्रांसप्लांट रजिस्ट्रेशन शामिल हैं। एसआईआर के हिस्से के तौर पर वोटरों द्वारा भरे गए गिनती के फ़ॉर्म में परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफ़िकेट उन डॉक्यूमेंट्स में शामिल था जिन्हें वोटर सुनवाई के दौरान जमा कर सकते थे। हालांकि, इस बात पर कन्फ्यूजन था कि क्या इन सर्टिफ़िकेट को आखिरकार रहने के वैध प्रमाण के तौर पर माना जाएगा। इस बारे में साफ़ जानकारी तब मिली, जब चुनाव आयोग ने बंगाल के चीफ़ इलेक्टोरल ऑफ़िसर (सीईओ) को पत्र लिखकर कन्फ़र्म किया कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफ़िकेट माने जाएंगे। पत्र में कहा गया था कि ''पश्चिम बंगाल राज्य में डोमिसाइल/परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफ़िकेट'' तभी माने जाएंगे जब वे ''डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/सब-डिवीज़नल ऑफ़िसर/कलेक्टर (कोलकाता)'' द्वारा जारी किए गए हों। कलेक्ट्रेट के अधिकारियों ने कहा कि एसआईआर के लिए खास तौर पर जारी किए गए डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट की संख्या को ट्रैक करना आसान था क्योंकि सर्टिफ़िकेट में उस मकसद का ज़िक्र होता है जिसके लिए इसे जारी किया गया है। एक अधिकारी ने कहा-24 दिसंबर से 9 फरवरी के बीच, हमने 16,925 डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट जारी किए। कुछ लोगों ने 24 दिसंबर से पहले ही सर्टिफ़िकेट ले लिए, यह सोचकर

कि उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। दिसंबर के आखिर से एप्लीकेशन बढ़ने लगे, और जनवरी के बीच में बहुत ज़्यादा आ गए। इस दौरान मिली एप्लीकेशन की संख्या काफी ज़्यादा थी, जिनमें से कई पुलिस वेरिफिकेशन के बाद रिजेक्ट हो गईं। अधिकारी ने कहा-हमें इस दौरान 19,167 एप्लीकेशन मिलीं। इससे पता चलता है कि 2,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गईं। हर एप्लीकेशन को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया और जो 15 साल की रेजिडेंसी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाईं, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ मामलों में, आवेदक ने बाद में अपनी रिक्वेस्ट वापस ले लीं, जबकि दूसरों को फॉर्म में गलतियों के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि ज़्यादातर एप्लीकेंट्स ''गरीब लोग'' थे, उनमें से कई दिहाड़ी मज़दूर थे जिनके पास एसआईआर हियरिंग के दौरान मांगे गए दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अधिकारी ने कहा-उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड और काउंसलर के सर्टिफिकेट जमा किए। कुछ ने किराए की रसीदें, रेंट एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की पुष्टि करने वाले डीड भी दिए। पुलिस ने उन इलाकों का खुद दौरा किया ताकि यह वेरिफाई किया जा सके कि एप्लीकेंट्स वहां 15 साल या उससे ज़्यादा समय से रह रहे थे। अधिकारी ने कहा कि एप्लीकेंट्स में शादी के बाद ससुराल जाने वाली महिलाओं की भी एक बड़ी संख्या थी। एसआईआर पीरियड के दौरान डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का प्रोसेस भी तेज़ कर दिया गया था। पहले, इस प्रोसेस में आम तौर पर 15 से 20 दिन लगते थे। एक अधिकारी ने कहा-औसतन, हमने एप्लीकेशन की तारीख से सात से आठ दिनों के अंदर सर्टिफिकेट जारी कर दिए और कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी आम तौर पर तेज़ी से मिल गईं। सर्टिफ़िकेट के लिए एप्लीकेशन या तो सीधे कलेक्टर ऑफ़िस में जमा किए गए या कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (कोलकाता नगर निगम) के ज़रिए भेजे गए। नगर निगम ने दिसंबर के आखिर से अपने हेडक्वार्टर और सभी बोरो ऑफ़िस में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि एप्लीकेंट कलेक्टर की वेबसाइट के सिटीज़न सर्विसेज़ सेक्शन से डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। भरा हुआ फ़ॉर्म डलहौज़ी में कलेक्टर ऑफ़िस में जमा करना होगा।

जिस युवती के साथ लगा दुष्कर्म का आरोप, उसी के साथ युवक ने की शादी

- बनगांव में सामने आया अनोखा मामला

निज संवाददाता : पॉक्सो केस में पिछले 16 महीनों से जेल में बंद 24 वर्षीय युवक ने कोर्ट परिसर में अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया। युवती अब 18 वर्ष की हो चुकी है। अदालत ने उसे जमानत देते हुए शादी की अनुमति प्रदान की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, दोनों के बीच संबंध तब शुरू हुए थे जब लड़की 16 साल की थी और युवक 22 वर्ष का था। 7 अक्तूबर 2024 को युवती के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए उस पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगाया। इसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। बीते बुधवार को सुनवाई के समय अदालत को बताया गया कि युवती अब बालिग है और दोनों परिवार इस रिश्ते को स्वीकार कर चुके हैं। दोनों पक्षों ने न्यायाधीश से विवाह की अनुमति देने का अनुरोध किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्लोल कुमार दास ने मानवीय पहलुओं और परिवारों की सहमति को ध्यान में रखते हुए याचिका स्वीकार कर ली। युवक को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई और उसे अपनी पत्नी के साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना न करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद परिवारजनों और वकीलों की मौजूदगी में विवाह संपन्न हुआ। युवती की मां ने अदालत के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि हम न्यायालय के निर्णय और सहयोग से अत्यंत खुश हैं। न्यायाधीश ने विवाह की अनुमति देने से पहले सभी के विचारों का सम्मान किया। हम स्थिति को लेकर चिंतित थे। अब हम केवल यही चाहते हैं कि वे एक साथ खुशी से रहें। दोनों शांतिपूर्वक और सुखद जीवन बिताएं। वहीं, बनगांव अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता सागर दास ने स्पष्ट किया कि चूंकि मामला पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया फिलहाल जारी रहेगी। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

बंगाल बजट में इमामों और मोअज़्ज़िनों का भत्ता नहीं बढ़ने से नाराज है मुस्लिम समुदाय

बढ़ सकती है ममता बनर्जी की चुनौती

निज संवाददाता : इस बार पश्चिम बंगाल के बजट में लक्ष्मी भंडार, आशा वर्कर्स से लेकर आंगनवाड़ी, सिविक वॉलंटियर्स सभी का भत्ता बढ़ा है। वहीं, बजट में इमामों और मोअज़्ज़िनों का भत्ता नहीं बढ़ा है। इससे मुस्लिम समुदाय के लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नाराज हैं। राज्य के अल्पसंख्यकों में ममता बनर्जी की सरकार को लेकर गुस्सा है।

2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27 फीसदी है, जो वर्तमान में करीब 34 फीसदी मानी जाती है। मुस्लिम ममता बनर्जी के बड़े वोटबैंक माने जाते हैं और इसी वोटबैंक के सहारे ममता बनर्जी चुनाव जीतती रही हैं, लेकिन चुनाव से पहले मुस्लिम नाराज हैं। इससे ममता बनर्जी की चुनौती बढ़ सकती है। बजट में आशा वर्कर्स का भत्ता 1000 रुपए बढ़ा है। उनका कहना है कि उन्हें इससे ज्यादा फायदा नहीं मिला है। मिड-डे मील वर्कर्स और पार्ट-टाइम टीचर्स भी खुश नहीं हैं। इस बार मोअज़्ज़िन भी गुस्से की लिस्ट में अपना नाम जोड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस समर्थित इमाम ऑर्गनाइजेशन के जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के अध्यक्ष और जलपाईगुड़ी गरल बारी मस्जिद के इमाम जहीरुल इस्लाम ने भत्ता नहीं बढ़ने पर नाराजगी जताई है। जहीरुल इस्लाम का कहना है कि इस बार राज्य बजट में सभी का भत्ता कमोबेश बढ़ाया गया है, लेकिन सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जिस रेट से कीमतें बढ़ी हैं, 3000 रुपये महीने के भत्ते से कुछ नहीं होता है, अगर यह कम से कम 500 रुपये भी बढ़ जाता, तो मैं समझ जाता कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नया सोचा है। जलपाईगुड़ी चरकडांगी जामा मस्जिद के मुअज़्ज़म अब्दुल मजीद ने कहना है कि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इस छोटे से भत्ते से कुछ नहीं होता। हमारा भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए था। वैसे, पुजारियों की तरह मुअज़्ज़िनों को भी हर महीने 1500 रुपये भत्ता मिलता है। दूसरी तरफ, इस्लामिक कम्युनिटी के लोगों के मन में गुस्सा भी बढ़ रहा है।

अजीदा खातून ने कहा कि इमाम दिन भर में बहुत से लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। उनका भत्ता क्यों नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? अनवर हुसैन, फजरुल हक ने कहा कि सरकार अभी इमामों को हर महीने करीब 1000 से 1300 रुपये देती है, लेकिन इस रकम से कुछ नहीं होता। महीने का भत्ता कम से कम 6-7 हजार रुपये होना चाहिए। तृणमूल से जुड़े इमाम संगठन के नेता के चेहरे पर भत्ता न बढ़ने से निराशा की खबर के बाद जलपाईगुड़ी का सियासी पारा चढ़ गया है। माकपा जिला सचिव समिति के सदस्य जमीनार अली का कहना है कि भले ही सभी का भत्ता कमोबेश बढ़ा दिया गया हो, लेकिन इमामों का भत्ता नहीं बढ़ाया गया है। यह भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए था। साथ ही, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राज्य के बजट को देखकर ऐसा लगता है कि यह तृणमूल का चुनावी घोषणा पत्र है। भत्ते की समस्या, नौकरियों की कमी, हर चीज का असर इस साल के चुनावों पर पड़ेगा। बीजेपी जिला समिति के सदस्य पांलेन घोष का कहना है कि बजट को लेकर समाज के कई वर्गों में गुस्सा बढ़ रहा है। इसका असर चुनावों पर जरूर पड़ेगा। इस बार तृणमूल सरकार का पतन निश्चित है। लेकिन, सत्तारूढ़ दल टीएमसी ने विपक्ष की बातों को खारिज कर दिया। तृणमूल डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर पॉल हसन प्रधान का कहना है कि हालांकि कई लोगों के अलाउंस बढ़ गए हैं, लेकिन इमाम और मुअज़्ज़न के अलाउंस नहीं बढ़े हैं। यह राज्य सरकार का मामला है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बारे में जरूर सोचेगी, लेकिन इससे वोट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि इमाम अलाउंस ममता ने ही शुरू किया था।

कोलकाता नगर निगम टाउन हॉल में बनाएगा डिजिटल लाइब्रेरी

मदद करेगी खड़गपुर आईआईटी की विशेषज्ञ टीम

निज संवाददाता : कोलकाता का इतिहास सिर्फ शहर का अतीत नहीं है, बल्कि इसकी पहचान का दस्तावेज भी है। ब्रिटिश काल से पहले के कोलकाता से लेकर अंग्रेजी शासन के काल तक और फिर आजादी के बाद महानगर के विकास तक-इस लंबी यात्रा की अनगिनत सूचनाएं, दस्तावेज और अभिलेख कोलकाता नगर निगम के अभिलेखागार में सावधानी से संरक्षित हैं। इस बार कोलकाता नगर निगम उस पारंपरिक अभिलेखागार को डिजिटल रूप में आम लोगों के सामने पेश करने की पहल कर रहा है। वार्ड नंबर 98 के तृणमूल पार्षद अरूप चक्रवर्ती ने हाल ही में नगर निगम के मासिक अधिवेशन में इस संबंध में प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव के जवाब में मेयर परिषद (संस्कृति एवं सूचना) देवाशीष कुमार ने कहा कि टाउन हॉल में अंतरराष्ट्रीय स्तर की डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। इस काम के लिए एक शुरुआती रिपोर्ट जमा कर दी गई है, जिसे आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों ने तैयार किया है। अरूप ने सेशन में कहा- कोलकाता के सोशियो-पॉलिटिकल इतिहास के कई कीमती डॉक्यूमेंट्स, जो एंटी-ब्रिटिश मूवमेंट से शुरू होते हैं, म्युनिसिपैलिटी के आर्काइव्स में हैं। इनमें से बहुत कुछ पहले ही डिजिटाइज़ हो चुका है। लेकिन वे अभी भी ज़्यादातर आर्काइव्स तक ही सीमित हैं। अगर इन डिजिटल कॉपीज़ को टाउन हॉल में रखा जाए, तो हिस्टोरिकल रिसर्च का दायरा और बढ़ेगा। ऐसे ही एक प्रपोज़ल के जवाब में, ज़िम्मेदार देवाशीष कुमार ने कहा-आईआईटी खड़गपुर को इस प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदारी दी गई थी। टेक्निकल आउटलाइन तैयार करने के अलावा, कई जाने-माने लोगों की एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार को फंड देने के लिए अप्लाई किया गया है। कोलकाता नगर निगम को उम्मीद है कि फंड मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। यह डिजिटल लाइब्रेरी सिर्फ़ मेट्रोपोलिस के इतिहास तक सीमित नहीं होगी। बांग्ला गाने, थिएटर, सिनेमा, स्पोर्ट्स समेत अलग-अलग कल्चरल जॉनर के इतिहास को अलग-अलग सेक्शन में हाईलाइट किया जाएगा। नगर निगम प्रशासन का मानना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए जानकारी को बचाकर रखने और दिखाने से शहर की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक ज़्यादा आसानी से पहुंच पाएगी।

अगर इतिहास को बचाकर रखने और उसे भविष्य के दरवाज़े तक पहुंचाने की यह पहल लागू होती है, तो टाउन हॉल कोलकाता की यादों का नया पता बन सकता है। इस दिन सेशन में मौजूद बीजेपी पार्षद विजय ओझा ने नगर निगम की इस पहल का स्वागत किया।

ऋत्विक घटक के पास फिल्में बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था

- कोलकाता साहित्य उत्सव में बोले फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा

निज संवाददाता : फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा ने कहा कि ऋत्विक घटक को ''आर्ट सिनेमा'' या ''पैरेलल सिनेमा'' जैसी कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता। उन्होंने कहा कि दिवंगत लेखक का काम अपनी बेबाक सिनेमाई भाषा और इतिहास और विस्थापन के साथ गहरे जुड़ाव के ज़रिए भारतीय फिल्ममेकिंग को आकार देता रहता है।

घटक की जन्म शताब्दी के मौके पर कोलकाता साहित्य उत्सव (केएलएम) में एक सेशन के दौरान बोलते हुए, मिश्रा ने कहा कि असल में सिर्फ़ दो तरह का सिनेमा होता है। उन्होंने कहा-एक जो खुद फिल्ममेकर से निकलता है और दूसरा जो सिनेमा के अलावा किसी और वजह से बनता है। घटक पूरी तरह से पहले वाले से जुड़े थे। मिश्रा ने घटक को एक ऐसा फिल्ममेकर बताया जिसके पास फिल्में बनाने के अलावा ''कोई चारा नहीं'' था, उन्होंने अपने निजी दर्द, राजनीतिक जागरूकता और कला की महारत को हर काम में उतारा, चाहे कमर्शियल रुकावटें हों या न हों। उन्होंने कहा-वह आपको सिखाते हैं कि सिनेमा क्या कर सकता हैफ्रेम के अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है, और इमेज और आवाज़ एक-दूसरे को कैसे काउंटरपॉइंट कर सकते हैं।

घटक को सिर्फ़ एक फ़ेस्टिवल फ़िल्ममेकर मानने की सोच को खारिज़ करते हुए, मिश्रा ने कहा कि मेघे ढाका तारा जैसी फ़िल्मों ने अपने समय में दर्शकों से जुड़ाव महसूस किया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि घटक के आराम या आसान समाधान देने से इनकार करने की वजह से अक्सर उनका काम बड़े पैमाने पर पॉपुलर नहीं हो पाया।

उन्होंने कहा-वह निराशा से मुंह नहीं मोड़ते। इसीलिए वह तुरंत पॉपुलर नहीं होते और इसीलिए वह टिके रहते हैं। मिश्रा ने कहा कि घटक का सिनेमा बंटवारे और माइग्रेशन के ट्रॉमा पर आधारित था, लेकिन राजनीति से आगे बढ़कर इंसानी हालत को गहराई से दिखाया गया। मिश्रा ने कहा-जब लोग माइग्रेट करते हैं, तो वे ज़मीन से ज़्यादा कुछ खो देते हैं। वे यादें, कल्चर, अपनापन खो देते हैं। यह दुख घटक के काम में दिखता है। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में विस्थापन के पैटर्न के बीच फ़िल्ममेकर की थीम आज भी रेलिवेंट हैं। मिश्रा ने सिनेमैटिक क्राफ्ट, खासकर साउंड डिज़ाइन और म्यूज़िक पर घटक के असर को भी बताया, और टैगोर, लोक परंपराओं और ऑडियो-विज़ुअल स्ट्रक्चर के उनके इस्तेमाल का ज़िक्र किया। मिश्रा ने कहा-हर बार जब आप कोई फ़िल्म बनाते हैं, तो कहीं न कहीं घटक मौजूद होते हैं। कोलकाता साहित्य उत्सव के घटक 100: ए सॉफ्ट नोट ऑन ए शार्प स्केल टाइटल वाले इस सेशन में राइटर-एडिटर शाम्या दासगुप्ता, पूर्व सूचना एवं प्रसारण अधिकारी निरुपमा कोटरू और लेखक सलिल त्रिपाठी ने बालाजी विट्टल के साथ बातचीत की। मिश्रा ने घटक को सत्यजीत रे जैसे उनके समय के लेखकों के सामने खड़ा करने की कोशिशों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि घटक ने खुद पाथेर पांचाली का सबसे अच्छा रिव्यू लिखा था। उन्होंने कहा-यहां कोई जंग नहीं है। घटक सिनेमा की भाषा में पहले से कहीं ज़्यादा मौजूद हैं।

पश्चिम बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट 28 फरवरी तक जारी होने की संभावना : सीईओ

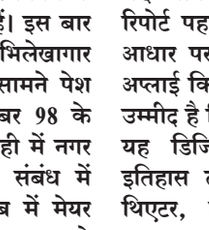

निज संवाददाता : बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट 21 फरवरी से पहले पब्लिश होने की उम्मीद नहीं है, हालांकि इसे महीने के आखिर तक जारी करने की कोशिशें चल रही हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 9 फरवरी को इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की डेडलाइन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी थी और प्रोसेस को पूरा करने में लगने वाले समय का हवाला देते हुए इसे 14 फरवरी से आगे बढ़ा दिया था। इस स्क्रूटनी का मकसद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (ईआरओ) को सही फैसले लेने में मदद करना है। अग्रवाल ने पत्रकारों से कहा-फाइनल वोटर लिस्ट 21 फरवरी से पहले पब्लिश नहीं होगी। हम इसे 28 फरवरी तक पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। रिवीजन प्रोसेस पर अपडेट देते हुए, उन्होंने कहा कि लगभग 1.39 करोड़ केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि लगभग 1.06 करोड़ केस में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा चुके हैं। अग्रवाल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव से जुड़े कामों के लिए 8,505 ग्रुप-बी ऑफिसर्स के नाम शेयर किए हैं। उन्होंने कहा-वे कल से जॉइन करेंगे। दो दिन की ट्रेनिंग के बाद, नए माइक्रो-ऑब्ज़र्वर को पांच से सात दिनों में उनके लॉग-इन क्रेडेंशियल मिल जाएंगे। शिकायत सुलझाने पर, सीईओ ने कहा-फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद, अगर किसी वोटर का नाम नहीं आता है, तो वे पांच दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर डीईओ एप्लीकेशन का निपटारा नहीं करते हैं, तो वोटर अगले पांच दिनों के अंदर स्टेट सीईओ से संपर्क कर सकते हैं।

चुनावी फर्जीवाड़ा का अनोखा मामला

जन्म प्रमाण पत्र ने वोटर लिस्ट की खोली पोल

निज संवाददाता : उत्तर 24 परगना जिले के बारानगर विधानसभा क्षेत्र के एक व्यक्ति पर राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की नज़र है, क्योंकि उसने हाल ही में संपन्न हुए मतदाता सूची संशोधन अभियान के दौरान कथित तौर पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। राज्य में इस अभियान के दौरान, संबंधित व्यक्ति ने एक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसकी जन्मतिथि 6 मार्च, 1993 दर्ज थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने इस पर आपत्ति जताई क्योंकि प्रमाण पत्र जन्म तिथि से दो दिन पहले, यानी 4 मार्च, 1993 को जारी किया गया था। जन्म से दो दिन पहले जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण असंभव मानते हुए, आयोग ने जल्द ही प्रमाण पत्र को अस्पष्ट घोषित कर दिया। इस मामले के चलते कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने मतदाता पंजीकरण अधिकारी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 का हवाला देते हुए चिन्हित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो झूठी जानकारी प्रस्तुत करने को दंडित करती है। इस बीच, पश्चिम बंगाल में राज्य चुनाव आयोग ने सत्यापन की अंतिम तिथि 21 फरवरी तय की है। आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। एसआईआर मामले की सुनवाई का लगभग पांच फीसदी हिस्सा अभी लंबित है। अंतिम मतदाता सूची, जो 14 फरवरी को जारी होनी थी, अब 21 फरवरी को जारी होगी।

कोलकाता एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम की धमकी

निज संवाददाता : कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह इंडिगो की एक फ्लाइट में बम की आशंका जताई गई, जिसके बाद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इंडिगो की फ्लाइट 6ई-7304 कोलकाता से मेघालय के शिलांग जा रही थी और इसे सुबह 9.15 बजे रवाना होना था। एक प्रेस विज्ञप्ति में अधिकारियों ने बताया कि विमान के शौचालय के अंदर चालक दल के सदस्यों को एक पत्र मिला, जिसके कारण बम की आशंका पैदा हुई। उन्होंने बताया कि यात्रियों के विमान में चढ़ने के दौरान यह पत्र बरामद हुआ। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अधिकारियों द्वारा तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। कोलकाता हवाई अड्डे के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा-बोर्डिंग के दौरान चालक दल के सदस्यों को विमान के शौचालय में एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें लिखा था कि विमान के अंदर बम है। इसके तुरंत बाद यात्रियों को विमान से उतार दिया गया। जांच प्रक्रिया जारी है।

बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार ने शुरू की 'युवा साथी' योजना

1 अप्रैल से होगी लागू

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए 'युवा साथी' योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा पास कर चुके और फिलहाल बेरोजगार युवाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अस्थायी सहारा देना है। पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना क्या है और इसमें किन लोगों को हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं? पश्चिम बंगाल की 'युवा साथी' योजना का लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो पश्चिम बंगाल के स्थायी निवासी हो, जिनकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच हो। वहीं जो माध्यमिक शिक्षा पास कर चुके हो, इसके अलावा आवेदन के समय बेरोजगार हो उन युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं या कुछ अन्य सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लाभार्थी कुछ निश्चित छात्रवृतियों के लिए पात्र बने रहेंगे। 'युवा साथी' योजना के तहत पात्र युवाओं को हर महीने 1500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यह सहायता अधिकतम 5 साल तक दी जाएगी यानी 1 साल में 18,000 रुपये और 5 साल में कुल 90 हजार रुपये तक की मदद मिलेगी। इसके अलावा 5 साल बाद इस योजना की समीक्षा की जाएगी, जिसमें अगर लाभार्थी तब तक बेरोजगार रहता है और आयु सीमा के अंदर है तो आगे सहायता जारी रखने का फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकार ने पहले इस योजना को अगस्त से लागू करने की बात कही थी, लेकिन बाद में घोषणा की गई कि योजना 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। आवेदन प्रक्रिया फरवरी से शुरू कर दी गई है। वहीं इस योजना के लिए राज्य की सभी 294 विधानसभा क्षेत्र में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इस योजना में आवेदन के लिए युवाओं को निर्धारित पोर्टल या शिविरों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन, पर्सनल जानकारी और बैंक डिटेल भरनी होगी। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, माध्यमिक अंक पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी शामिल होगी। फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन आईडी के जरिए कंडीशन ट्रैक भी की जा सकेगी।

हल करो हीरो बनो का उत्तर

1)फास्फोरस, 2)कोबाल्ट, 3)1995, 4)विटामिन बी12, 5)मस्तिष्क

संपादकीय

बांग्लादेश चुनाव और बदलते परिदृश्य में दिल्ली-ढाका रिश्तों का भविष्य

लोगों के भारी विरोध व कई तरह की अशांति के बाद शेख हसीना सरकार के हटने के अठारह महीने बाद, बांग्लादेश ने अपने अगले नेताओं को चुनने के लिए वोट किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 300 में से 209 सीटें हासिल करके दो-तिहाई बहुमत हासिल किया है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने 68 सीटें जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी नेशनल सिटिजन पार्टी, जिसका नेतृत्व शेख हसीना के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रहने वाले एक्टिविस्ट कर रहे थे, ने छह सीटें जीतीं। इसके अलावा, 60 फीसदी से ज़्यादा वोटरों ने चुनाव के साथ हुए एक रेफरेंडम के तहत प्रस्तावित बड़े सुधारों के पक्ष में वोट दिया। हालांकि जमात ने कुछ चुनाव क्षेत्रों में वोटों में हेरफेर के आरोपों पर पहले ही चिंता जताई है, लेकिन कुल मिलाकर, चुनाव ने ज़्यादातर बांग्लादेशियों की नज़र में ज़रूरी मान्यता हासिल कर ली है। बांग्लादेश, भारत और दूसरे पड़ोसियों के लिए, यह बड़ी राहत की बात होनी चाहिए। भारत के नज़रिए से बीएनपी की साफ़ जीत एक ऐसे रिश्ते को फिर से ठीक करने का मौका है जो नई दिल्ली के सामरिक फ़ायदों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हसीना को हटाने के बाद से इस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पहले से, भारत के बीएनपी के साथ ज़्यादातर रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन पहले के उलट, बीएनपी अब जमात के साथ अलायंस में नहीं है, जो एक पाकिस्तान-समर्थक ताकत है, जिसके साथ भारत को कोई भी काम करने में मुश्किल होती। बीएनपी नेता, तारिक रहमान ने एक ऐसा बांग्लादेश बनाने का वादा किया है जो सबको साथ लेकर चलने वाला हो और अपनी माइनॉरिटी को सम्मान और सुरक्षा दे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि वह भारत के पड़ोसियों का पक्ष नहीं लेंगेयह एक ऐसी नीति है जिसे नई दिल्ली मान सकती है। जबकि भारत ने पारंपरिक रूप से बांग्लादेश में हसीना की अवामी लीग को सत्ता में देखना पसंद किया है, पार्टी को इन चुनावों से बैन कर दिया गया था। इसकी गैरमौजूदगी में, बीएनपी और तारिक रहमान ऐसे जाने-माने लोग हैं जिनके साथ काम करने के लिए भारत खुद पर भरोसा करेगा। असल में, भारत बीएनपी के साथ रिश्ते फिर से बना रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया, जो तारिक रहमान की मां भी हैं, के अंतिम संस्कार के लिए ढाका भेजा गया था। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रहमान के बीच तुरंत हुई बधाई कॉल का मकसद उस गति को और बढ़ाना है।फिर भी बांग्लादेश और भारत के अपने पूर्वी पड़ोसी के साथ रिश्तों के लिए, चुनाव और उसके नतीजे नॉर्मल हालात की ओर पहला कदम ही हैं। एक ऐतिहासिक चुनाव में सिर्फ़ 60 फीसदी वोटिंग होना बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा के मौजूदा माहौल और अवामी लीग के समर्थकों को अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डालने का मौका न देने का एक सबूत है। तारिक रहमान के सामने अब जनमत संग्रह में किए गए सुधारों को पूरा करने का मुश्किल काम है। इसका मतलब होगा दूसरे बदलावों के साथ-साथ प्रधानमंत्री की शक्तियों को सीमित करना। और नई दिल्ली द्वारा सुलह की कोशिशों के बावजूद, शेख हसीना के लिए भारत का लंबे समय से समर्थन और उनका भारत में लगातार रहना कई बांग्लादेशियों के लिए दुख की बात बनी हुई है। ये विवादित मुद्दे हैं जिन पर नई दिल्ली और ढाका की नई सरकार को काम करने की ज़रूरत है। दोनों पक्षों को समझदारी, सब्र और असलियत दिखानी चाहिए: बदलते पड़ोस में भारत और बांग्लादेश को एक-दूसरे की ज़रूरत है।

डिजिटल लत के साये में बचपन

टूटती जिंदगियां और भारत की अधूरी सोशल मीडिया सुरक्षा नीति

भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां बच्चों की दुनिया तेजी से बदल रही है। खिलौनों, मैदानों और दोस्तों की जगह मोबाइल स्क्रीन ने ले ली है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे-धीरे हमारी आंखों के सामने पनपा। गाजियाबाद की तीन नाबालिग बहनों और भोपाल के एक 14 साल के बच्चे की मौत ने इस सच्चाई को बेरहमी से उजागर कर दिया है कि डिजिटल दुनिया अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रही, बल्कि कई मासूम जिंदगियों के लिए मानसिक जाल बन चुकी है। ये घटनाएं कोई इत्तेफाक नहीं हैं, बल्कि उस सिस्टम का नतीजा हैं जहां बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा अहमियत डिजिटल मुनाफे को दी जा रही है। भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच ने पिछले एक दशक में क्रांति ला दी। सरकारी और निजी रिपोर्टों के मुताबिक आज देश में 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं और इनमें करीब एक तिहाई बच्चे और किशोर हैं। एक औसत भारतीय बच्चा रोजाना 3 से 6 घंटे स्क्रीन पर बिता रहा है। कोरोना महामारी के दौरान यह समय और बढ़ा। ऑनलाइन पढ़ाई ने मोबाइल को बच्चों की जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बना दिया। लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद वही मोबाइल गेमिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैलेंज का प्रवेश द्वार बन गया। धीरे-धीरे बच्चों के लिए असली दुनिया उबाऊ और स्क्रीन के भीतर की दुनिया ज्यादा आकर्षक लगने लगी। ऑनलाइन गेमिंग का मनोविज्ञान बेहद जटिल है। कई गेम्स और टास्क-बेस्ड ऑनलाइन ट्रेंड इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि यूजर को लगातार अगला स्तर पूरा करने की बेचैनी बनी रहे। हर टास्क पूरा होने पर दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो खुशी और संतुष्टि का एहसास देता है। यही प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है और लत बन जाती है। बच्चों का दिमाग, जो अभी विकास की अवस्था में होता है, इस प्रभाव को समझ नहीं पाता। वे यह फर्क नहीं कर पाते कि गेम का दबाव और असली जिंदगी की अहमियत क्या है। गाजियाबाद की तीनों बहनों के मामले में भी शुरुआती जांच यही संकेत देती है कि वे एक टास्क-बेस्ड ऑनलाइन गेम से भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी थीं, जहां गेम पूरा करना ही उनका लक्ष्य बन गया था। समस्या सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। रील्स, शॉर्ट वीडियो और लाइक-शेयर का सिस्टम बच्चों को लंबे समय तक स्क्रीन से बांधे रखता है। कंपनियों का मुनाफा यूजर के समय पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा समय बच्चा स्क्रीन पर रहेगा, उतना ज्यादा डेटा, उतना ज्यादा विज्ञापन और उतनी ज्यादा कमाई। लेकिन इस दौड़ में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की कीमत कोई नहीं गिनता। भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए बच्चों की सुरक्षा को लेकर नियम तो हैं, लेकिन वे या तो अधूरे हैं या सख्ती से लागू नहीं होते। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि डिजिटल एडिक्शन बच्चों में अकेलापन, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और अवसाद को बढ़ाता है। कई अध्ययनों में यह सामने आया है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों के व्यवहार में आक्रामकता और सामाजिक दूरी पैदा करता है। बच्चे परिवार से कटने लगते हैं और ऑनलाइन दुनिया में मिले अनजान लोगों या कैरेक्टर्स से ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। यही स्थिति उन्हें आसानी से मैनिपुलेट होने के खतरे में डाल देती है। ब्लू व्हेल, मोमो चैलेंज या अन्य टास्क-बेस्ड ट्रेंड इसी मानसिक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। दुनिया के कई देशों ने इस खतरे को गंभीरता से लिया है। चीन ने बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त समय सीमा तय की है। वहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे तय घंटों से ज्यादा गेम नहीं खेल सकते। दक्षिण कोरिया ने भी रात के समय बच्चों के गेमिंग पर रोक जैसे नियम लागू किए। यूरोप के कई देशों में सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों के डेटा और मानसिक सुरक्षा के लिए जवाबदेह ठहराया गया है। वहां उम्र सत्यापन, कंटेंट फिल्टर और पैरेंटल कंट्रोल को अनिवार्य बनाया गया है। इसके उलट भारत में ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस और स्पष्ट नीति अब भी अधूरी है। माता-पिता की भूमिका भी इस संकट में अहम है, लेकिन उन्हें पूरी तरह दोषी ठहराना सही नहीं होगा। बदलती तकनीक की रफ्तार के साथ पैरेंट्स खुद जूझ रहे हैं। कई बार वे बच्चों की ऑनलाइन भाषा, गेम्स या प्लेटफॉर्म्स को समझ ही नहीं पाते। जब समस्या नजर आती है, तब तक हालात बिगड़ चुके होते हैं। डांट, मोबाइल छीनना या सख्ती अक्सर बच्चों को और ज्यादा दूर धकेल देती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि संवाद, भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि वे अपनी उलझनें परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। यह सवाल अब टालने लायक नहीं रहा कि क्या भारत को भी बच्चों के लिए सख्त सोशल मीडिया और गेमिंग नीति की जरूरत है। क्या उम्र सत्यापन को मजबूत नहीं किया जाना चाहिए। क्या कंपनियों को यह जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि उनके प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित हों। जब दूसरे देश यह कर सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं। डिजिटल दुनिया से बच्चों को पूरी तरह दूर करना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें बिना सुरक्षा के छोड़ देना भी एक तरह की लापरवाही है। गाजियाबाद और भोपाल की घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि तकनीक जितनी ताकतवर है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है, अगर उसका इस्तेमाल बिना संतुलन के हो। यह सिर्फ एक परिवार या एक शहर की कहानी नहीं है। यह पूरे समाज के लिए चेतावनी है। अगर अब भी नीति, समाज और परिवार एक साथ नहीं आए, तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। तब हमारे पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बच्चों का भविष्य डिजिटल बाजार के हवाले करना सबसे बड़ा जोखिम है, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जानें अपना राशिफल

मेष
गुणकारी समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, अचानक कोई बड़ा काम करने का अवसर मिल सकता है जो फायदेमंद होगा, मन प्रसन्न रहेगा।

वृषभ
अस्त–व्यस्त समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं सोच समझकर ही करे, कोई परिवार का सदस्य आपका समय खराब कर सकता है, मन वश में रखे।

मिथुन
सुखद समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, जीवनसाथी पूरा साथ दे सकते हैं, मन में उत्साह रहेगा।

कर्क
अपेक्षा रखकर काम करने वाला समय हो सकता है, कोई बड़ा काम करने का अवसर मिल सकता है जो फायदेमंद होगा, पूरी नैतिकता से काम करने की आवश्यकता है, मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह
काया कष्ट वाला समय हो सकता है इसलिए पूरी सावधानी रखकर काम करने की आवश्यकता है, लापरवाही करने से चोट लग सकती है सावधान रहे, आपसी सहमति बनाये रखे, मन चंचल रहेगा।

कन्या
निश्चिन्त रहकर काम करने वाला समय हो सकता है, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, मन प्रसन्न रहेगा।

तुला
मनचला समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं सोच समझकर ही करे, ज्यादा खर्च परेशानी का कारण बन सकता है, अपनी बुद्धिमानी दिखाने की आवश्यकता है, मन स्थिर रखें।

वृश्चिक
सदुपयोग करने वाला समय हो सकता है, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, किसी नये व्यक्ति से काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करे, मन में उत्साह रहेगा।

धनु
उपासना करने वाला समय हो सकता है, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, अपनी सोच सकारात्मक रखने की जरूरत है, मन शान्त रखें।

मकर
निस्वार्थ भाव रखकर काम करने वाला समय हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य पूरा साथ दे सकता है, पूरी नैतिकता से काम करने की आवश्यकता है, मन प्रसन्न रहेगा।

कुंभ
हौसला रखकर काम करने वाला समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करे, अपनी बुद्धिमानी से काम करने की आवश्यकता है, मन प्रसन्न रहेगा।

मीन
बुलंद समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, कोई रुका हुआ जमीन का काम आगे बढ़ सकता है, अपने परिवार को प्रसन्न रखे, मन स्थिर रखें।

मासूम बच्चे की मासूमियत

एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका -हारा घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसका पांच वर्षीय बेटा सोने की बजाये उसका इंतज़ार कर रहा है। अन्दर घुसते ही बेटे ने पूछा पापा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ-हाँ पूछो, क्या पूछना है? पिता ने कहा। बेटा- पापा, आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। बेटा, मैं बस यूँही जानना चाहता हूँ। बताइए कि आप एक घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100रुपये। अच्छा, बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा- पापा क्या आप मुझे 50 रूपये उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा, तो तुम इसीलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या उटपटांग चीज खरीद सको। चुप चाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने सेलफिस हो मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीजों में बर्बाद करना चाहते हो, यह सुन बेटे की आँखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे कि ऐसा करने कि हिम्मत कैसे हुई पर एक-आध घंटा बीतने के बाद वह थोडा शांत हुआ, और सोचने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे ने सच -में किसी जरूरी काम के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठ कर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो?'नहीं 'जवाब आया। मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हे डांट दिया, दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था। व्यक्ति ने कहा, माफ करना ये लो अपने पचास रूपये ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में पचास की नोट रख दी। धन्यवाद पापा, बेटा ख़ुशी से पैसे लेते हुए कहा, और फिर वह तेजी से उठकर अपनी आलमारी की तरफ गया, वहां से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे-धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देख व्यक्ति फिर से क्रोधित होने लगा, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, पर अब पूरे हैं बेटे ने कहा। पापा अब मेरे पास 100 रूपये हैं। क्या मैं आपका एक घंटा खरीद सकता हूँ? आप ये पैसे ले लीजिये और कल घर जल्दी आ जाइये, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तेज रफ़्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना ब्यस्त कर लेते हैं कि उन लोगो के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस आपा-धापी में भी हम अपने माँ-बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी अहसास होगा कि हमने छोटी-मोटी चीजें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया।

सच्चा दोस्त

एक घने जंगल में एक हिरण और खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे। हिरण का नाम था चंचल और खरगोश का नाम था बुद्ध। चंचल अपनी तेज़ी और सुंदरता के लिए जाना जाता था, जबकि बुद्ध अपनी चतुराई के लिए। वे दोनों रोज़ जंगल में खेलते और एक-दूसरे का साथ बहुत एन्जॉय करते। एक दिन, जब वे खेल रहे थे, एक शिकारी ने चंचल को देखा और उसे पकड़ने की सोची। शिकारी ने चुपके से चंचल के पास जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया। चंचल जाल में फंस गया और बहुत डर गया। उसने बुद्ध को मदद के लिए पुकारा। बुद्धू ने देखा कि चंचल मुसीबत में है और उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह शिकारी के पास गया और उसे दूसरी दिशा में भटकाने लगा। बुद्धू ने शिकारी को दूर एक और हिरण के होने का झूठा विश्वास दिलाया। शिकारी बुद्ध के झांसे में आ गया और उस दिशा में चला गया। इस बीच, बुद्ध ने चंचल को जाल से मुक्त कर दिया। जब शिकारी वापस आया, तो उसने देखा कि चंचल जाल से गायब था। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उधर, चंचल और बुद्ध जंगल की गहराई में भाग गए और सुरक्षित थे। इस घटना के बाद, चंचल और बुद्ध की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। चंचल ने बुद्ध की चतुराई और साहस की बहुत प्रशंसा की। बुद्ध ने चंचल से कहा, ''दोस्ती में सबसे बड़ी बात एक-दूसरे की मदद करना है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।'' इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय में आपका साथ नहीं छोड़ता और हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। चंचल और बुद्ध की कहानी आज भी जंगल में सच्ची दोस्ती की मिसाल के रूप में सुनाई जाती है।

हल करो हीरो बनो

1. पौधों में जड़ विकास के लिए मुख्य रुप से कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है।
(क) नाईट्रोजन (ख) पोटैशियम
(ग) फास्फोरस (घ) कोल्शियम

2. निम्नलिखित में से किस तत्व से समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है।
(क) यूरेनियम (ख) कोबाल्ट
(ग) सोडियम (घ) आयोडिन

3. यकृत, दूध, अण्डे और मछली सहित विभिन्न खाद्ध पदार्थो में पाया जाने वाला कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन आपके शरीर के रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है?
(क) विटामिन सी (ख) विटामिन बी12
(ग) विटामिन ए (घ) विटामिन ई

4. मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है।
(क) गुर्दा (ख) यकृत
(ग) हृदय (घ) मस्तिष्क

(उत्तर इसी अंक में)

माथापच्ची–20

1	8	4		9	7		6	
	7			1		9	2	
			6				7	
7								6
		3				1		
2								5
	2				3			
	5	8		2			1	
	9		4	5		7	3	2

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक है, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी एवं खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते। उत्तर अगले अंक में

माथापच्ची 19 का हल

5	8	9	1	2	7	6	3	4
1	4	6	3	9	5	8	2	7
3	2	7	6	8	4	1	5	9
8	7	1	5	3	6	4	9	2
6	5	2	7	4	9	3	8	1
4	9	3	8	1	2	5	7	6
9	6	5	4	7	8	2	1	3
2	1	4	9	5	3	7	6	8
7	3	8	2	6	1	9	4	5

मार लो मुस्की

भिखारी- एक अदमी मुझसे पूछ रहा था कि मैं कितना कमा लेता हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला और चुप रहा,
दूसरा भिखारी- ऐसा क्यों?
भिखारी- मुझे शक था कि कहीं ये इनकम टैक्स वाला तो नहीं है!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पापा- बेटा तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ?
चिंटू- पापा 80% आए हैं।
पापा- लेकिन मार्कशीट पर तो सिर्फ 40% लिखा है?
चिंटू- बाकी के 40% आधारकार्ड लिंक होने पर सीधे अकाउंट में आएंगे। दे चप्पल, दे चप्पल।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

उपदेशक: अगर गधे को शराब और पानी दोनों पीने को दिये जाये तो गधा क्या पियेगा।
शराबी: जाहिर है पानी पियेगा
उपदेशक: क्यों?
शराबी: क्योंकि वो गधा है।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

साल के आखिरी दिनों में लोग माफी तो ऐसे मांग रहे हैं, जैसे कि...नए साल में सबकुछ छोड़कर संन्यास लेके हरिद्वार जा रहें हैं!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर उसे 5:58 पर उठकर बंद करके वापस सोने में....
ऐसी फीलिंग आती हैं जैसे बम डिफ्यूज कर दिया हो..

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। तौलिया है, साबुन है, बाल्टी है, डब्बा है, पानी है पर...
नहाने की हिम्मत नहीं है। वैसे नहाने से कुछ नहीं होता, आदमी दिल का साफ़ होना चाहिये। इतनी सर्दी में नहाना अपनी समझ से तो बाहर है। जिस शब्द में ही आगे न है और पीछे ना है तो बीच में ये दुनिया हाँ कराने पर क्यों तुली है ??

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

हुआ अपहरण ''धूप'' का, पूरी जनता मौन, कोहरा ''थानेदार'' है, रपट लिखाए कौन?
''ऐ सर्दी'' तू इतना मत इतरा है हिम्मत तो जून में आ।
वाह, वाह! शायरी खत्म चलता हूँ अब रजाई में।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

जिंदगी से परेशान एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, ''हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी हैं, उठा ले मुझे!'' भगवान ने यमदूत को नीचे भेजा।
यमदूत बोला- तुमने याद किया और मैं आ गया।
यमदूत को सामने देखकर आदमी घबराकर बोला, ''अब मैं खुद पर गुस्सा भी नहीं कर सकता हूं क्या?''

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

अकबर ने बीरबल से सवाल किया: आदमी और औरत की सोच में क्या फर्क है ?
बीरबल ने बहुत चतुर जवाब दिया: औरत एक ही आदमी से बहुत सारी उम्मीद रखती है ...
और आदमी बहुत सारी औरतो से एक ही उम्मीद रखता है !!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

हमारे देश में अरबी बोली नही जाती, बल्कि खाई जाती है।
चीनी भी बोली नहीं जाती, सिर्फ़ खाई जाती है। उसी तरह अंग्रेजी भी उतनी बोली नही जाती, जितनी पी जाती है..!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

संता: भाई, आज मैंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया!
बंता: वह कैसे?
संता: मैंने 10 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया।
बंता: अरे वाह! पर उसमें लिखा क्या था?
संता: वह तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ हेडलाइंस देख रहा था!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

लक्ष्य सर्वांगीण विकास होना चाहिए, परीक्षा पास करना नहीं

परीक्षा पर चर्चा 2026

डॉ. मनोज कुमार तिवारी

प्रधानमंत्री ने कहा कि हर छात्र अद्वितीय है। उनकी अपनी क्षमता, विशेषता, जीवनशैली, सोचने समझने का ढंग अलग- अलग होता है, इसलिए विद्यार्थियों का परीक्षा की तैयारी का तरीका अलग-अलग हो सकता है।

परीक्षा पर चर्चा 2026 (नवें संस्करण) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कुशल मनोवैज्ञानिक की भांति विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा की। उन्होंने सीधे परीक्षा तनाव पर चर्चा करने के बजाय छात्रों के जीवन व उनके क्षेत्र से संबंधित विभिन्न आयामों पर चर्चा की, जिससे छात्र उनसे सीधे जुड़ सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर छात्र अद्वितीय है। उनकी अपनी क्षमता, विशेषता, जीवनशैली, सोचने समझने का ढंग अलग- अलग होता है, इसलिए विद्यार्थियों का परीक्षा की तैयारी का तरीका अलग-अलग हो सकता है। उन्होंने छात्रों से कहा कि अपनी परीक्षा की तैयारी अपने ढंग से करनी चाहिए, सभी के सुझाव को सुनना चाहिए किंतु अपनी तैयारी का पैटर्न अपने अनुभव के अनुसार तय करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन में ज्ञान एवं कौशल दोनों महत्वपूर्ण है-एक के बिना दूसरे का काम चलने वाला नहीं है। इसलिए अध्ययन एवं प्रशिक्षण दोनों जीवन में आवश्यक है। उन्होंने छात्रों से कहा कि हमें बीते हुए कल पर नहीं बल्कि अपने वर्तमान एवं भविष्य पर अधिक फोकस करके अपने विकास की तैयारी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा की प्रश्न-पत्र उन विद्यार्थियों को ही कठिन लगता है जो पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी न करके सिर्फ परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयारी करतें हैं। उन्होंने कहा कि मन को मजबूत एवं स्वस्थ रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना के शरीर को स्वास्थ्य व मजबूत रखना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जीवन परीक्षा के लिए नहीं है बल्कि परीक्षा जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों को परीक्षा को बोझ व मजबूरी के रूप में न लेकर जीवन के विकास के लिए आवश्यक मानकर तैयारी करना चाहिए, जीवन में अंकों का उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना की हमारे जीवन में हमारे ज्ञान व कौशल का होता है। भूलने की समस्या पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थी जितनी अधिक सलंग्नता के साथ अध्ययन करेगा भूलना उतना ही कम होगा। छात्रों को लिखकर अभ्यास करने की सलाह दी, क्योंकि लिखकर सीखी गई विषयवस्तु का विस्मरण कम होता है। विद्यार्थियों को आपस में विषय पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के माध्यम से अधिगम मजबूत होता है तथा संप्रत्यय की समझ स्पष्ट होती है। अभिभावकों को चाहिए कि वह बच्चे को उनकी रुचि क्षमता के अनुसार अवसर व संसाधन उपलब्ध करायें ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाना चाहिए कमजोरी नहीं। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को संदेश दिया है छात्रों को प्रश्न पत्र के अभ्यास पर बल देने के बजाय संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ने पर जोर देना चाहिए ताकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आए तो विद्यार्थी आसानी से हल कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय व्यवस्थापन जीवन की हर अवस्था में महत्वपूर्ण होता है। छात्र जीवन में यह अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समय व्यवस्थापन से न केवल श्रम व ऊर्जा की बचत होती है बल्कि सुव्यवस्थित विकास होता है।

विद्यार्थियों को चाहिए कि वह घर के सदस्यों से भी परीक्षा पर चर्चा करके परीक्षा तनाव को प्रबंध करें। परीक्षा हाल में तनाव अधिक होने पर लंबी गहरी सांस लेना अत्यंत लाभदायक होता है। विद्यार्थी को महान लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए तथा उसे अपने आप को जोड़ना चाहिए। इससे निराशा एवं हताशा कम होती है परीक्षा की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वदेशी, राष्ट्र प्रेम, जीवनशैली, विकसित भारत, स्वच्छता अभियान, अपने कर्तव्यों का पालन करने तथा तकनीकी के सही उपयोग पर भी बल दिया।

निपाह वायरस से बंगाल में पहली मौत

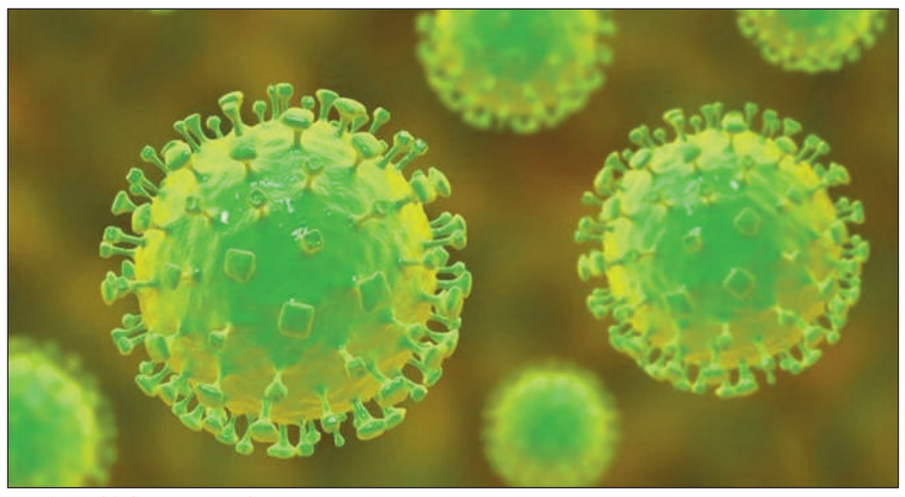

कई दिनों के इलाज के बाद नर्स ने तोड़ा दम

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से संक्रमित महिला नर्स की मौत हो गई। बीते गुरुवार दोपहर बारासात के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। जनवरी के आखिर में उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया था। हालांकि वह कई तरह की दिक्कतों से जूझ रही थी। सूत्रों के मुताबिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। लंबे समय तक कोमा में रहने की वजह से उसकी इम्यूनिटी भी कम हो गई थी। ऊपर से उसे फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। गुरुवार दोपहर उसकी मौत हो गई। दरअसल इस साल की शुरुआत में इस राज्य में निपाह इन्फेक्शन की खबर आई थी। उत्तर 24 परगना के एक मेल नर्स और एक फीमेल नर्स के इन्फेक्टेड होने की खबर के बाद दहशत फैल गई। युवा नर्स 31 दिसंबर को अंग्रेजी नए साल की छुट्टियों में घर गई थी। वह पिछली जनवरी के पहले हफ्ते में बीमार पड़ गई थी। उसे पहले बर्दवान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और बाद में बारासात के उस प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां वह काम करती थी। वहीं उसका इलाज चल रहा था। टेस्ट में पता चला कि वह निपाह वायरस से इन्फेक्टेड थी। उसी समय प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का भाई भी निपाह पॉजिटिव पाया गया। उसका भी उसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। हालांकि इलाज का असर दिखने के बाद वह कुछ दिन पहले ठीक होकर घर लौट आई। इस बीच, पूर्व बर्दवान के कटवा की रहने वाली 25 साल की महिला नर्स वेंटिलेशन से हटाए जाने के बाद भी कोमा में थी।

उसे नोसोकोमियल इन्फेक्शन (अस्पताल-जनित संक्रमण) बताया गया था। वह अपनी आंखें खोलने, शरीर को तानने, हाथ-पैर हिलाने और बोलने की भी कोशिश कर रही थी। अचानक बीते दिन उसकी हालत बिगड़ गई। गुरुवार शाम करीब 4:20 बजे बारासात के उस प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई।

महाशिवरात्रि : अंधकार से आत्मबोध तक की शिव-यात्रा

साल 2026 में महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026, रविवार को मनाई जाएगी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी, रविवार को शाम 5 बजकर 4 मिनट से शुरू होगी। यह तिथि 16 फरवरी, सोमवार को शाम 5 बजकर 34 मिनट तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि रात्रि में पड़ने के कारण 15 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन किया जाएगा

डा. पंकज भारद्वाज

सनातन चेतना में महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की दिव्य रात्रि है। यह वह क्षण है जब साधक बाह्य संसार की चंचलता से हटकर अंतर्मन में उतरता है और शिव-तत्त्व का अनुभव करता है। 'शिव' का अर्थ ही है कल्याण। जहां शिव हैं, वहां भय, द्वंद्व और अज्ञान का स्थान नहीं रहता। आज के भौतिकतावादी और तनावग्रस्त युग में महाशिवरात्रि का महत्व और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि यह पर्व मनुष्य को बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब प्रकृति स्थिर होती है और चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। योगशास्त्र के अनुसार इस रात्रि पृथ्वी की ऊर्जा मानव शरीर में सहज रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यही कारण है कि इस रात्रि ध्यान, मौन और साधना विशेष फलदायी माने गए हैं। शिव को आदियोगी कहा गया है वे प्रथम गुरु हैं, जिन्होंने मानवता को योग, ध्यान और आत्मानुशासन का मार्ग दिखाया। आज का मनुष्य भी प्रतिदिन हलाहल विष का सामना कर रहा है, जैसे- कार्य का दबाव, प्रतिस्पर्धा, रिश्तों में खटास, अकेलापन, उपभोग की

असीम चाह और भविष्य की अनिश्चितता। यह विष धीरे-धीरे मन को अशांत, शरीर को रोगी और आत्मा को थका हुआ बना देता है। समुद्र मंथन की कथा केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत रूपक है। जैसे देवताओं और दानवों के प्रयास से पहले विष निकला, वैसे ही जीवन में परिवर्तन और प्रगति से पहले संघर्ष और पीड़ा आती है। भगवान शिव का विषपान यह संदेश देता है कि जो चेतना में स्थिर है, वही विष को अमृत में बदल सकती है।

शिव पूजन बाह्य नहीं, अंतःयात्रा

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पूजन का आध्यात्मिक अर्थ अत्यंत गूढ़ है। शिवलिंग निराकार और साकार के मिलन का प्रतीक है। जब भक्त जल अर्पित करता है, तो वह अपने चंचल विचारों को शांत करता है; दूध अर्पण कर वह अपनी कठोरता को कोमलता में बदलता है। बेलपत्र अर्पण कर वह अपने तीन दोष काम, क्रोध और लोभ का विसर्जन करता है। आज के समय में शिव पूजन का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार, अधैर्य और असंतोष को त्यागना। यही सच्ची आराधना है। महाशिवरात्रि का रात्रि जागरण केवल आंखों का जागना नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। यह आत्मनिरीक्षण की रात्रि है, मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है और मैं किन विषों को ढो रहा हूं? आज जब समाज अवसाद, हिंसा और असहिष्णुता से जूझ रहा है, तब शिव का मौन और वैराग्य हमें सिखाता है कि हर समस्या का उत्तर शोर में नहीं, स्थिरता में छिपा है। भगवान शिव आशुतोष हैं वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे भाव को देखते हैं, प्रदर्शन को नहीं। आज जब आडंबर और दिखावे ने साधना को भी प्रभावित किया है, शिव हमें सरलता और सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। एक क्षण का सच्चा ध्यान, एक आंसू भरी प्रार्थना, एक मौन स्वीकार यह सब शिव को प्रिय है। महाशिवरात्रि हमें यह स्मरण कराती है कि शिव मंदिर में ही नहीं, हमारे भीतर भी विराजमान हैं। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता, क्रोध और भय को स्वीकार कर उसे चेतना के कंठ में रोक लेते हैं, तब जीवन नीलकंठ बन जाता है। विष रहते हुए भी करुणा और संतुलन से भरा। महाशिवरात्रि पर्व आत्मा को शिवमय करने का अवसर है। ये बाहरी अंधकार से नहीं, भीतरी प्रकाश से जीवन को बदलने का पर्व है।

बीस साल बाद फिर मायावती का दलित-ब्राह्मण-मुस्लिम गठजोड़ फार्मूला

निज संवाददाता : उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी करीब 15 सालों से सत्ता से बाहर है। 2007 से 2012 तक सत्ता में रही बसपा को पिछले तीन विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान तीन लोकसभा चुनाव में भी बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसके बाद से बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में यह धारणा आम तौर पर बनने लगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती का कालखंड खत्म हो चुका है। ऐसा इसलिये भी कहा जा रहा था क्योंकि मायावती ने चुनाव प्रचार से भी काफी हद तक किनारा कर लिया था। बात अंतिम बार 2007 में विधानसभा चुनाव जीती बसपा की उस समय की चुनावी रणनीति की की जाये तो 2007 का चुनाव मायावती सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले से जीती थी। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने राजनीतिक इतिहास रच दिया। 2007 में मायावती ने सामाजिक समीकरण साधकर 403 सीटों में से 206 सीटों पर कब्जा जमाया और कुल 30.43 प्रतिशत वोट हासिल किए। बसपा सुप्रीमो की यह जीत दलितों के परंपरागत वोट बैंक के अलावा ब्राह्मणों और कुछ गैर-यादव पिछड़ी जातियों तथा मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से संभव हुई थी। यह और बात है कि इसके बाद मायावती का यह फार्मूला दोबारा परवान नहीं चढ़ पाया। बहरहाल, अबकी करीब 20 सालों के बाद एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिये बसपा के पक्ष में दलितों के साथ ब्राह्मणों एवं मुसलमानों के वोटों की गोलबंदी देखी जा रही है। ब्राह्मणों और मुसलमानों के एक बार फिर बसपा की तरफ रुख करने की वजह में जाया जाए तो ऐसा लगता है कि योगी राज में ब्राह्मणों को लग रहा है कि उनके साथ यह सरकार नाइंसाफी कर रही है। नौकरशाही से लेकर सरकार तक में महत्वपूर्ण पदों से ब्राह्मणों को दूर रखा गया है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में ब्राह्मण नेताओं का प्रवेश अधिक देखा गया है। जनवरी 2026 में अंबेडकर नगर से भाजपा के दिग्गज नेता राधेश्याम पांडे 51-100 ब्राह्मण समर्थकों के साथ बसपा में शामिल हुए। उन्होंने मायावती से मुलाकात कर पार्टी जॉइन की। दिसंबर 2025 में ब्राह्मण समाज के बड़े नेता जैसे जितेंद्र मिश्रा, दीपक द्विवेदी, नीरज पांडे, विशाल मिश्रा, वैभव दुबे, अनुराग शुक्ला, मोहित शर्मा भाजपा से बसपा में शामिल हुए। यह 2027 चुनाव से पहले भाजपा को झटका था। जनवरी 2026 में एक अन्य बड़े ब्राह्मण नेता ने मायावती से मुलाकात कर बसपा जॉइन की।

वहीं मुसलमान इसलिये बसपा की तरफ फिर से मुड़ता दिख रहा है क्योंकि उसे लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों से वोट तो लेती है, लेकिन उनका (मुसलमानों का) हक उन्हें नहीं दिया जाता है। इसी तरह से मुसीबत के समय भी अखिलेश मुसलमानों से दूरी बना लेते हैं। पार्टी के दिग्गज

नेता आजम खान को अकेला छोड़ देना इसकी सबसे बड़ी मिसाल बताते हैं। बाहुबली अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की भी मौत के लिये मुस्लिम समाज कहीं न कहीं अखिलेश यादव को जिम्मेदार मानते हैं। उन्हें लगता है कि विधानसभा सत्र के दौरान अखिलेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अतीक और मुख्तार को लेकर उकसाया नहीं होता तो आज वह जिंदा होते। दलित वोटरों ने बसपा को पूर्ण समर्थन दिया। जाटव समुदाय के 86 प्रतिशत मतदाताओं ने मायावती को चुना, जबकि वाल्मीकि जाति के 71 प्रतिशत ने पार्टी को तरजीह दी। पासी समुदाय से 53 प्रतिशत और अन्य अनुसूचित जातियों से 58 प्रतिशत वोट बसपा के खाते में आए। इन दलित उपजातियों की मजबूत पकड़ ने पार्टी को आधार प्रदान किया, क्योंकि दलित उत्तर प्रदेश की आबादी में करीब 21 प्रतिशत हैं। ऊपरी जातियों में ब्राह्मणों का 16 प्रतिशत समर्थन मिला, जो निर्णायक साबित हुआ। बसपा ने 51 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 20 जीते, लेकिन यह जीत मुख्यतः निचली जातियों के वोटों से आई। ठाकुरों और अन्य ऊपरी जातियों ने भी सीमित लेकिन महत्वपूर्ण योगदान दिया। पिछड़ी जातियों ने भी बसपा की ओर रुख किया। गैर-यादव और गैर-कुर्मी अन्य पिछड़ा वर्ग के 30 प्रतिशत मतदाताओं ने पार्टी चुनी। कुल पिछड़ा वर्ग के कई खंडों से वोट उमड़े, जिसने सामाजिक समीकरण को मजबूत बनाया। बसपा ने 110 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार मैदान में उतारे। यह समर्थन समाजवादी पार्टी और अन्य दलों से छिटके वोटरों का परिणाम था, जो विकास और सुशासन के वादों से प्रभावित हुए। मुस्लिम मतदाताओं का योगदान सबसे चमत्कारिक रहा। 2007 में बसपा को कुल वोटों में मुस्लिम वोट 10 प्रतिशत से अधिक थे।

एक सर्वे के अनुसार 17 प्रतिशत मुस्लिमों ने पार्टी को समर्थन दिया। पार्टी ने 61 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 29 विधायक बने। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19 प्रतिशत होने के बावजूद यह समर्थन बहुमत के लिए जरूरी साबित हुआ। समाजवादी पार्टी से नाराज मुस्लिमों ने बसपा को मौका दिया, क्योंकि मायावती ने अल्पसंख्यक कल्याण के वादे किए। मायावती की रणनीति ने जातिगत बंधनों को तोड़ा। दलित-ब्राह्मण गठजोड़ की बात भले ही प्रचारित हुई, लेकिन वास्तव में जाटव, वाल्मीकि, पासी जैसे दलितों के साथ अन्य अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्ग के 30 प्रतिशत, ब्राह्मणों के 16 प्रतिशत और मुस्लिमों के 17 प्रतिशत वोटों ने चमत्कार रचा। बसपा का वोट प्रतिशत 2002 के 23 से बढ़कर 30 हो गया। पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों से ऊपरी जातियों को लुभाया, जबकि मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया। यह जीत सामाजिक न्याय की मिसाल बनी। मायावती ने सत्ता में आकर अपराध पर अंकुश लगाया और विकास कार्य तेज किए। लेकिन जातिगत समीकरण की बारीकी ने राजनीति को नया आयाम दिया। दलितों का कोर वोट 80-86 प्रतिशत तक रहा, ऊपरी जातियों से 16-20 उम्मीदवार जीते, पिछड़ों से 30 प्रतिशत समर्थन और मुस्लिमों के 17 प्रतिशत ने पूर्ण बहुमत सुनिश्चित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती किस तरह से पंडित कार्ड खेल रही हैं, इसका ताजा उदाहरण यह बताता है कि उनका ब्राह्मणों के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है। मायावती ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नये नियमों को लेकर सवर्णों, विशेषकर ब्राह्मणों की नाराजगी के बाद से चल रही राजनीति पर और इसके बाद बॉलीवुड फिल्म 'घूसखोर पंडित' के खिलाफ ब्राह्मणों के पक्ष में बयान देने में देरी नहीं की। इससे पहले यूजीसी के नये नियम पर संयमित प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा था कि इस नये कानून से किसी को बिना वजह प्रताड़ित नहीं किया जाये। देश भर में 'घूसखोर पंडित' फिल्म के विरोध के बीच बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। वहीं यूजीसी प्रकरण में असहज हुई भाजपा भी अब फिल्म के मुद्दे पर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म पर एफआईआर के निर्देश देकर इस वर्ग के साथ का संदेश दिया। बसपा प्रमुख ने इस मामले में शुक्रवार 06 फरवरी को एक्स पर लिखा-यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं, बल्कि अब तो फिल्मों में भी 'पंडित' को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है, जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस जातिसूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, यह बसपा की मांग है।' वर्ष 2007 में बसपा ने ब्राह्मणों के साथ सोशल इंजीनियरिंग का दांव चला था और बहुमत की सरकार बनाई थी। इस बार भी बसपा उसी फार्मूले पर चुनावी तैयारी में जुटी है और पार्टी प्रमुख के एक्स पोस्ट को उसी रणनीति को आगे बढ़ाने का संकेत माना जा रहा है।

वैद्यनाथ धाम से पशुपतिनाथ को जोड़ेगा हाई-स्पीड कॉरिडोर

14 घंटे का सफर 3 घंटे में पूरा होगा

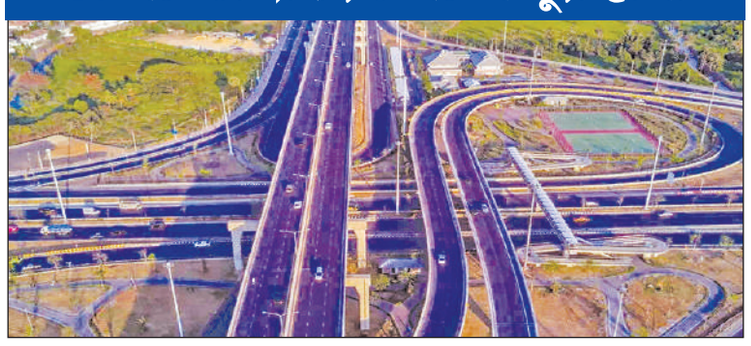

निज संवाददाता : भारत सरकार देश के भीतर एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के बाद अब पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम को नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से जोड़ने के लिए एक हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बिहार के सड़क निर्माण मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने इस परियोजना की पुष्टि करते हुए बताया कि झारखंड से नेपाल तक एक्सप्रेसवे बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे न केवल दो देशों को जोड़ेगा, बल्कि दो अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के बीच की दूरी कम कर देगा। जो सफर 14 घंटे का होता है वो सिर्फ 3 घंटे का रह जाएगा। बिहार सरकार ने अपने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सड़क निर्माण के लिए 8,260 करोड़ रुपये का भारी-भरकम आवंटन किया है, जिसमें पशुपतिनाथ-वैद्यनाथ धाम हाई-स्पीड कॉरिडोर को प्राथमिकता दी गई है।

प्रस्तावित योजना के अनुसार, यह एक्सप्रेसवे नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू होगा और भारत में बिहार के सुपौल जिले के रास्ते प्रवेश करेगा। नेपाल के भीतर यह कॉरिडोर भीमनगर और बीरपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही पहले के मुकाबले काफी सुगम हो जाएगी। लगभग 250 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का मार्ग सामरिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। काठमांडू से शुरू होकर यह कॉरिडोर बिहार के सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर और बांका जिलों से होकर गुजरेगा। इन जिलों के जुड़ने से न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि बिहार और झारखंड के इन पिछड़े इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। एक्सप्रेसवे का अंतिम पड़ाव झारखंड का देवघर जिला होगा, जहां यह बाबा वैद्यनाथ धाम को सीधा संपर्क प्रदान करेगा। बिहार सरकार ने इस परियोजना का विस्तृत प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र से हरी झंडी मिलते ही जमीन अधिग्रहण और निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक साझेदारी को मजबूत करना है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो वर्तमान में बाबा वैद्यनाथ धाम से पशुपतिनाथ की दूरी लगभग 534 किलोमीटर है, जिसे तय करने में सड़क मार्ग से 13 से 14 घंटे का समय लगता है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह दूरी घटकर केवल 250 किलोमीटर रह जाएगी और यात्री महज 2 से 3 घंटे में अपना सफर पूरा कर सकेंगे। इससे ईंधन और समय की बड़ी बचत होगी। सड़क निर्माण मंत्री के अनुसार, भारत-नेपाल सीमा पर अब तक 554 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। यदि केंद्र सरकार से इस नए एक्सप्रेसवे को समय पर मंजूरी मिल जाती है, तो उम्मीद है कि यह ऐतिहासिक प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और पर्यटन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा।

बंगाल से सटे बांग्लादेश के इलाकों में जमात-ए-इस्लामी की भारी जीत ने बढ़ाई चिंता

♦ 25 साल में सबसे मजबूत चुनावी प्रदर्शन

निज संवाददाता : बांग्लादेश में हुए आम चुनाव के नतीजों ने भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा से लगे इलाकों में नई चिंता पैदा कर दी है। शुक्रवार को आए परिणामों में कट्टर रुख वाली पार्टी जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगियों ने सीमा से लगे कई इलाकों में अच्छी सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि 68 सीटों वाले जिन क्षेत्रों में कड़ा मुकाबला था, वहां जमात और उसके साथियों ने उल्लेखनीय जीत दर्ज की। कुल मिलाकर यह प्रदर्शन पिछले 25 साल से अधिक समय में जमात का सबसे मजबूत चुनावी प्रदर्शन माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जमात-ए-इस्लामी का इतिहास और उसका वैचारिक झुकाव पाकिस्तान के करीब माना जाता रहा है, इसलिए उसके उभार को भारत की सुरक्षा नजर से भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर चिंता जताई है। पार्टी का कहना है कि सीमा के दोनों ओर कट्टर सोच का फैलाव भविष्य के लिए चुनौती बन सकता है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि बांग्लादेश एक अलग देश है और वहां की नई सरकार से उम्मीद है कि वह कानून व्यवस्था मजबूत रखेगी और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सीमा के पास जमात की जीत चिंता का विषय है और यह दिखाता है कि सीमा के दोनों ओर कट्टर सोच को समर्थन मिल रहा है। उनके अनुसार भारत को इस स्थिति पर नजर रखनी होगी और सीमा प्रबंधन को और मजबूत करना होगा। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल के कई जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा उन बांग्लादेशी इलाकों से लगती है जहां जमात को सफलता मिली है। इनमें दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा और अलीपुरद्वार प्रमुख हैं। इन जिलों में पहले भी सीमा पार आवागमन, तस्करी और अवैध गतिविधियों को लेकर चर्चा होती रही है। अब राजनीतिक बदलाव ने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान फिर से इन क्षेत्रों पर केंद्रित कर दिया है। बांग्लादेश के भीतर देखें तो जमात ने पश्चिमी हिस्से के कई इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाया है। सतखीरा, मयमनसिंह, राजशाही, रंगपुर और गाइबांधा जैसे इलाकों में पार्टी की पैठ मजबूत होती दिख रही है। स्थानीय जानकारों का कहना है कि पिछले एक साल में जमात ने जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय किया और समाज के कुछ वर्गों में समर्थन जुटाया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि जमात ने अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अपना असर फैलाया।

हिमाचल प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

31 मई से पहले करवाना होगा पंचायत चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने सुक्खू सरकार को राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 31 मई से पहले करवाने का आदेश दिया, हाईकोर्ट ने पहले 30 अप्रैल की डेडलाइन दी थी। 31 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया है और सुक्खू सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति की है।

निज संवाददाता : हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। 31 मई से पहले हर हाल में पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के फैसले को सुक्खू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है और अब हिमाचल प्रदेश में 31 मई से पहले पंचायत चुनाव करवाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस यमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और फैसला सुनाया। इससे पहले, हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुक्खू सरकार को एक महीने की और मोहल्लत दी है। जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। 31 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल को चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। लेकिन सरकार ने एलएसपी डालकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक हर हाल में आरक्षण रोस्टर जारी करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, चार फरवरी को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अपनी एसएलपी पर सरकार ने दो तर्क दिए थे और कहा था कि हाईकोर्ट ने सरकार को चुनाव का रोस्टर जारी करने के लिए केवल चार दिन दिए हैं। जबकि इसी तरह के एक मामले में 2021 में रोस्टर जारी के बाद आपत्तियां सुनने के लिए अन्य खंडपीठ ने तीन महीने का समय दिया था। ऐसे में दोनों फैसलों को लेकर विरोधाभास देखने को मिला था। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2025 में पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन सरकार ने आपदा का बहाना बनाते हुए चुनाव टालने की कोशिश की थी। तब से इस मामले पर हिमाचल प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए थे। बात में हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुक्खू सरकार ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन फिर यूटर्न लिया और चुनौती दी।

वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती ताकत

वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका एक संतुलनकारी शक्ति से बढ़कर एक निर्णायक नेतृत्व की ओर बढ़ रही है

सुरेश सिंह बैस "शाश्वत"

2026 की शुरुआत में खड़ा विश्व एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर है जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी पुरानी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और शक्ति के ध्रुवीकरण के इस दौर में, वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका एक संतुलनकारी शक्ति से बढ़कर एक निर्णायक नेतृत्व की ओर बढ़ रही है।

आज की विश्व व्यवस्था अब एक ध्रुवीय नहीं रही। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, रूस-यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने वैश्विक संस्थानों (जैसे यूएन और डब्ल्यूटीओ) की सीमाओं को उजागर कर दिया है। दुनिया अब कई शक्ति केंद्रों में विभाजित हो रही है, जहां मध्यम शक्तियां अपनी स्वायत्तता की तलाश में हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाएं वर्तमान संकटों को सुलझाने में विफल दिख रही हैं, जिससे सुधारित बहुपक्षवाद की मांग तेज हुई है। इन सब विषमताओं के बीच भारत की अपनी आर्थिक सुदृढ़ीकरण और वैश्विक नेतृत्व का उभार भारत को विश्व नेता के रूप में सामने प्रस्तुत कर रहा है।

भारत ने खुद को विकासशील और अल्पविकसित देशों के प्रतिनिधि के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। जनवरी 2026 से भारत ने ब्रिक्स की कमान संभाली है। भारत का लक्ष्य इस मंच को पश्चिम-विरोधी बनाने के बजाय एक समावेशी वैश्विक मंच के रूप में विकसित करना है। भारत की विदेश नीति अब केवल राष्ट्रीय हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है, जैसा कि कोविड-19 के दौरान वैक्सीन मैत्री और तुर्की-सीरिया भूकंप में ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से देखा गया। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक नेतृत्व के दावों को ठोस आधार प्रदान करती है। अनुमान है कि भारत जल्द ही जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत ने किसी भी गुट का हिस्सा बने बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखी है। वह एक तरफ क्वाड के जरिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस और मध्य-पूर्व के देशों के साथ ऊर्जा और रणनीतिक संबंध भी मजबूत कर रहा है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई और आधार, आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है। कई देश भारत की इस तकनीक को अपना रहे हैं, जिससे भारत सॉफ्ट पावर के साथ-साथ टेक पावर के रूप में भी उभर रहा है।

चीन के साथ सीमा विवाद और अस्थिर पड़ोस (पाकिस्तान, म्यांमार) भारत की ऊर्जा को डायवर्ट करते हैं। वैश्विक अस्थिरता के बीच अपनी विशाल आबादी के लिए निरंतर और सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। वैश्विक नेतृत्व के लिए बुनियादी ढांचे और अनुसंधान (आर एंड डी) में भारी निवेश की निरंतर आवश्यकता है। भारत अब नियम फालो करने वाला देश नहीं, बल्कि नियम बनाने वाला राष्ट्र बन रहा है। 2026 का यह वर्ष भारत के लिए अपनी वैश्विक साख को और गहरा करने का स्वर्णिम अवसर है।

जी20 क्षेत्र में दुनिया को एकजुट करने के लिए इस गठबंधन की शुरुआत हुई, जो पर्यावरण संरक्षण में भारत की अग्रणी भूमिका को दर्शाता है। भारत ने 2023 की अपनी अध्यक्षता के दौरान जी20 की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत ने इसे केवल आर्थिक चर्चा का मंच न रखकर एक जन-आंदोलन बना दिया। अफ्रीकी संघ को सदस्यता मिलना भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत अफ्रीकी संघ को जी20 का स्थायी सदस्य बनाना थी। इससे भारत ने साबित किया कि वह ग्लोबल साउथ का वास्तविक नेता है।

भारत ने दुनिया को दिखाया कि कैसे डिजिटल तकनीक (यूपीआई, आधार) का उपयोग वित्तीय समावेशन के लिए किया जा सकता है।

अब इंडिया स्टैक कई विकासशील देशों के लिए एक रोल मॉडल है। 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता एक ऐसे समय में आई है जब दुनिया डी-डलरलाइजेशन (डॉलर पर निर्भरता कम करने) और वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों की बात कर रही है। ब्रिक्स के नए सदस्यों (जैसे मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई) के आने के बाद, भारत की भूमिका इन विविध हितों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स पे भारत अपनी डिजिटल भुगतान तकनीक के माध्यम से ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने का नेतृत्व कर रहा है। ब्रिक्स के भीतर चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए भारत एक लोकतांत्रिक और पारदर्शी विकल्प पेश करता है, जिससे यह समूह केवल एक पश्चिम-विरोधी गुट बनने के बजाय एक विकास-केंद्रित मंच बना रहे।

कुल मिलाकर भारत अब केवल मेज पर बैठने की मांग नहीं कर रहा, बल्कि वह अब एजेंडा तय कर रहा है। वैश्विक ऋण संकट हो या खाद्य सुरक्षा, दुनिया अब समाधान के लिए नई दिल्ली की ओर देखती है।

2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की बिसात

योगी का बजट

आंकड़ों के सहारे सियासी दांव

निज संवाददाता : उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट केवल अगले वित्त वर्ष की आय-व्यय योजना नहीं है, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की सबसे ठोस राजनीतिक पटकथा के रूप में देखा जा रहा है। 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये के इस बजट के जरिए सरकार ने यह साफ संकेत दिया है कि वह चुनाव से पहले विकास, सुरक्षा और कल्याण तीनों मोर्चों पर अपने दावों को आंकड़ों के साथ जमीन पर उतारकर पेश करना चाहती है। पिछले बजट के मुकाबले करीब 12.9 प्रतिशत बढ़े इस आकार को सत्ता पक्ष "विश्वास का बजट" बता रहा है, जबकि इसके भीतर छिपा राजनीतिक संदेश यह है कि सरकार न तो संसाधनों की कमी से जूझ रही है और न ही चुनाव से पहले खर्च बढ़ाने से पीछे हट रही है।

सरकार ने सबसे पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपने मजबूत पक्ष के रूप में सामने रखा है। 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार 30.25 लाख करोड़ रुपये की जीएसडीपी और 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर यह दिखाने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश अब केवल जनसंख्या वाला राज्य नहीं, बल्कि तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन चुका है। 2016-17 में जहां जीएसडीपी करीब 12.75 लाख करोड़ रुपये थी, वहीं आठ-नौ वर्षों में इसके ढाई गुना से अधिक होने को सरकार स्थिर शासन और निवेश के अनुकूल माहौल का नतीजा बता रही है। 2027 के चुनाव में यह आंकड़ा खासतौर पर शहरी मतदाताओं, कारोबारियों और निवेश से जुड़े वर्गों के सामने रखा जाएगा, ताकि यह संदेश जाए कि सत्ता में बदलाव विकास की रफ्तार को रोक सकता है।

प्रति व्यक्ति आय को लेकर दिए गए आंकड़े भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं। 2016-17 में 54,564 रुपये रही प्रति व्यक्ति आय के 2024-25 में बढ़कर 1,09,844 रुपये होने और 2025-26 में इसके 1,20,000 रुपये तक पहुंचने के अनुमान को सरकार आम आदमी की जिंदगी से जोड़कर पेश कर रही है। यह संदेश खास तौर पर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए है, जो महंगाई, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य खर्च को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। सरकार का दावा है कि आय बढ़ने का मतलब सिर्फ आंकड़ों में सुधार नहीं, बल्कि उपभोग और जीवन स्तर में बदलाव है। गरीबी के मोर्चे पर 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का दावा 2027 के लिहाज से सबसे बड़ा सामाजिक कार्ड माना जा रहा है। मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत कार्ड, शौचालय और बिजली कनेक्शन जैसी योजनाओं से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों को एक साथ रखकर सरकार यह दिखाना चाहती है कि गरीब सिर्फ योजनाओं का नाम नहीं, बल्कि सत्ता की राजनीति का केंद्र है। चुनावी रणनीति में यह वर्ग इसलिए अहम है क्योंकि यह सीधे सरकार से जुड़ाव महसूस करता है और उसके फैसले अक्सर स्थिर रहते हैं।

रोजगार को लेकर बजट में पेश किए गए आंकड़े विपक्ष के सबसे मजबूत मुद्दे का जवाब माने जा रहे हैं। बेरोजगारी दर 2.24 प्रतिशत बताकर सरकार यह दावा कर रही है कि प्रदेश में रोजगार की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। पुलिस विभाग में 2017 से अब तक 2 लाख 19 हजार से अधिक भर्तियां, 1 लाख 58 हजार पदोन्नतियां, 60 हजार से ज्यादा प्रशिक्षणाधीन जवान और 83 हजार से अधिक पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को एक साथ जोड़कर सरकार यह दिखाना चाहती है कि सरकारी नौकरियां सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहीं। शिक्षा क्षेत्र में 34 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति भी इसी दिशा में रखा गया कदम है, क्योंकि शिक्षक समुदाय ग्रामीण और कस्बाई राजनीति में राय बनाने की अहम भूमिका निभाता है। युवाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की रणनीति भी बजट में साफ दिखती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बिना गारंटी और बिना ब्याज ऋण देकर हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका राजनीतिक मतलब यह है कि सरकार उन युवाओं को भी साधना चाहती है, जिन्हें सरकारी नौकरी की सीमित सीटों से निराशा हुई है। अगर यह योजना आंशिक रूप से भी सफल होती है, तो 2027 तक लाखों परिवार सीधे इससे जुड़ सकते हैं। कृषि क्षेत्र के आंकड़े ग्रामीण राजनीति को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। 3 लाख 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र में सरकार का सबसे मजबूत चुनावी हथियार माना जा रहा है। गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से करीब 3000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लाभ का दावा किसानों को यह याद दिलाने के लिए है कि भुगतान सीधे खाते में पहुंचा है। गेहूं, धान और मोटे अनाज की लाखों मीट्रिक टन खरीद और हजारों करोड़ रुपये के भुगतान के आंकड़े न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश हैं। नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था ग्रामीण मतदाताओं के लिए सीधा संदेश है कि सिंचाई लागत सरकार उठाने को तैयार है। महिलाओं को लेकर बजट में दिए गए आंकड़े 2022 के चुनावी अनुभव से निकले हुए माने जा रहे हैं, जहां महिला मतदाताओं का झुकाव निर्णायक साबित हुआ था। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत 26.81 लाख बालिकाओं को लाभ, सेफ सिटी परियोजना, महिला पुलिस बीट, सीसीटीवी नेटवर्क और वर्किंग वूमेन हॉस्टल जैसे प्रावधान यह दिखाते हैं कि सरकार महिला सुरक्षा और सम्मान को केवल कानून-व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दा मानती है। महिला मतदाता भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों आधारों पर निर्णय करती हैं, और बजट में यह संदेश उसी दिशा में जाता है।

कानून-व्यवस्था से जुड़े आंकड़े भी 2027 की चुनावी कहानी का अहम हिस्सा हैं। डकैती, लूट, हत्या और अपहरण जैसे अपराधों में 40 से 80 प्रतिशत तक कमी के दावे के जरिए सरकार यह स्थापित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश अब पहले जैसा असुरक्षित नहीं है। पुलिस भवनों, आवास और संसाधनों पर हजारों करोड़ रुपये के प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया जाएगा।

यह संदेश शहरी मतदाताओं, व्यापारियों और महिलाओं के लिए खास तौर पर अहम है। कुल मिलाकर 2026-27 का बजट एक ऐसा दस्तावेज बनकर सामने आया है, जिसमें हर बड़ा आंकड़ा 2027 के मतदाता को ध्यान में रखकर चुना गया है। विकास, कल्याण, सुरक्षा और पहचान चारों को जोड़कर सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि सत्ता की निरंतरता ही स्थिरता की गारंटी है। आने वाले महीनों में यही बजट गांव-गांव, शहर-शहर होने वाली राजनीतिक बहसों का आधार बनेगा, जहां सरकार इन आंकड़ों के सहारे भरोसा मांगेगी और विपक्ष इन्हीं आंकड़ों को चुनौती देने की कोशिश करेगा।

'गॉड पार्टिकल' के जनक महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस

जिनको जीवन में वह पहचान व सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे

प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर उनके कार्य ने बोस-आइंस्टीन संघनन की नींव रखी, जो पदार्थ की एक नई अवस्था है जिसमें हजारों परमाणु संघनित होकर एक विशाल परमाणु बनाते हैं जो तरंग की तरह व्यवहार करता है। बोस के सांख्यिकी का पालन करने वाले कणों को उनके सम्मान में बोसॉन नाम दिया गया है। बोस को ईश्वर कण का जनक (गॉड पार्टिकल) कहा जाता है।

निज संवाददाता : भारत के महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस को अपने जीवन में वह पहचान व सम्मान नहीं मिली, जिसके वह असल में हकदार थे। उन्होंने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर काम किया था और बोस-आइंस्टाइन सिद्धांत दिया था। उन्होंने एक सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की थी। जिसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस को सम्मान देने के लिए बोसॉन रखा गया था। जन्म और परिवारपश्चिम बंगाल के कोलकाता में 01 जनवरी 1894 को सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुरेंद्रनाथ बोस था, जोकि ईस्टप इंडियन रेलवे में काम करते थे। इन्होंने अपनी शुरूआती शिक्षा जुगलिया गांव से पूरी की थी। फिर कोलकाता के प्रेजिडेंसी कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी से एमए किया था। उन्होंने बांग्ला भाषा में बहुत लेखन किया और आइंस्टीन के मूल जर्मन शोधकार्यों के आधार पर वह अंग्रेजी की एक किताब के सहलेखक भी बने थे।शोधपत्रजब सत्येंद्र नाथ बोस ढाका यूनिवर्सिटी में थे, तब साल 1924 में उन्होंने एक शोधपत्र लिखा था। इनमें बोस ने प्लैंक का क्वांटम रेडिएशन सिद्धांत निकाला। इसके लिए बोस ने शास्त्रीय भौतिकी का संदर्भ नहीं लिया था। बोस ने इस शोध को जर्मनी अल्बर्ट आइंस्टीन को भेजा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके महत्व को पहचाना और उसका जर्मन में अनुवाद किया और वहां के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल में बोस के नाम से इसको प्रकाशित कराया।बड़े वैज्ञानिकों के साथ कामइसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस यूरोप गए और दो साल तक एक्स रे और क्रिस्टलोग्राफी प्रयोगशालाओं में काम किया। यहां पर उन्होंने आइंस्टीन और मैडम क्यूरी समेत कई वैज्ञानिको के साथ काम किया। वहीं खुद आइंस्टीन ने भी बोस के आइडिया को अपनाया और उसको परमाणुओं पर लागू करके ऐसे कणों के समूह की खोज की, जिसको बोसोन कहा जाता है। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकीगैस के अणुओं की गति के गणित के लिए मैक्सवेल और बोल्ट्समैन द्वारा एक सांख्यिकी की खोज की थी। जो परमाणुओं के लेवल तक काम करती थी। परमाणु के अंदर उपपरमाणु कणों की जानकारी के बाद यह सांख्यिकी उस लेवल पर नाकाम साबित हुई। इनके लिए सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा नई सांख्यिकी खोजी गई। इसको ही बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। गॉड पार्टिकलवहीं साल 2012 में जब गॉड पार्टिकल की खोज की गई, तब बोस के नाम पर वैज्ञानिकों ने उसको हिग्स-बोसोन कण नाम दिया। फिर जुलाई 2012 के न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में बोस को फादर ऑफ गॉड पार्टिकल बताया गया। यह भौतिकी का मूलभूत कण है, जोकि हिग्स क्षेत्र में क्वांटम उत्तेजन से पैदा होता है। 4 फरवरी 1974 में सत्येंद्रनाथ बोस का निधन हो गया था।

ऑर्बिट स्नूपिंग : अंतरिक्ष में नई तरह की जासूसी की शुरुआत

पहली बार भारत की किसी निजी कंपनी ने यह क्षमता दिखाई

निज संवाददाता : अंतरिक्ष अब सिर्फ खोज और विज्ञान की जगह नहीं रहा, संचार, मौसम, रक्षा और नेविगेशन सब कुछ सैटेलाइट पर निर्भर है। ऐसे में क्या कोई देश अंतरिक्ष में घूम रहे दूसरे सैटेलाइट के बिल्कुल पास जाकर उसकी तस्वीरें ले सकता है? इसे ही कहा जाता है ऑर्बिट स्नूपिंग। हाल ही में भारत की एक निजी कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की तस्वीरें लेकर इस क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसे अंतरिक्ष में नई तरह की जासूसी की शुरुआत माना जाता है।

ऑर्बिट स्नूपिंग

ऑर्बिट स्नूपिंग या इन-ऑर्बिट सर्विलांस ऐसी तकनीक है जिसमें एक सैटेलाइट जानबूझकर दूसरे सैटेलाइट या अंतरिक्ष स्टेशन के पास जाकर उसकी गतिविधियों की निगरानी करता है। आम सैटेलाइट पृथ्वी की तस्वीरें लेते हैं, लेकिन इस तकनीक में लक्ष्य अंतरिक्ष में मौजूद दूसरी वस्तुएं होती हैं।

इसका मकसद सिर्फ तस्वीर लेना नहीं, बल्कि यह समझना भी होता है कि दूसरा सैटेलाइट क्या कर रहा है, उसकी बनावट कैसी है और वह किस तरह काम कर रहा है। इसे स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस का हिस्सा माना जाता है, यानी अंतरिक्ष में क्या हो रहा है इसकी सटीक जानकारी रखना। अहमदाबाद की निजी कंपनी अजिस्टा स्पेस ने 3 फरवरी को एक अहम प्रयोग किया। कंपनी के करीब 80 किलोग्राम वजनी एएफआर सैटेलाइट, जिसे एबीए फर्स्ट रनर कहा जाता है, ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस की तस्वीरें लीं। आईएसएस पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में घूमता है। एएफआर सैटेलाइट ने करीब 250 से 300 किलोमीटर की दूरी से आईएसएस को दो बार ट्रैक किया और कुल 15 तस्वीरें लीं। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट तेज रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे। तस्वीरें सूरज की विपरीत दिशा से ली गईं, ताकि साफ इमेज मिल सके। यह पहली बार है जब भारत की किसी निजी कंपनी ने अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे स्पेसक्राफ्ट को ट्रैक कर उसकी तस्वीरें लेने की क्षमता दिखाई है। आज भारत के 50 से ज्यादा सैटेलाइट अलग-अलग कक्षाओं में काम कर रहे हैं और उनकी कुल कीमत हजारों करोड़ रुपये है। ऐसे में अंतरिक्ष में मौजूद अपने एसेट्स की सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है।

ऑर्बिट स्नूपिंग जैसी तकनीक से यह पता लगाया जा सकता है कि कोई विदेशी सैटेलाइट भारतीय सैटेलाइट के पास तो नहीं आ रहा या उसकी गतिविधियां संदिग्ध तो नहीं हैं। यह मिसाइल ट्रैकिंग और संभावित खतरे की पहचान में भी मदद कर सकती है। अंतरिक्ष में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इसे भविष्य की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तकनीकी रूप से देखें तो किसी सैटेलाइट के पास जाकर उसकी तस्वीर लेना निगरानी की श्रेणी में आता है। हालांकि अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय कानूनों के दायरे में है और वहां गतिविधियां खुले तौर पर ट्रैक की जाती हैं।

दुनिया की बड़ी स्पेस ताकतें, जैसे अमेरिका, रूस और चीन, पहले से ही स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम विकसित कर चुकी हैं। भारत भी धीरे-धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भारत के पास कितनी क्षमता?

भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और रक्षा क्षेत्र में काम कर रही संस्थाएं पहले से ही अंतरिक्ष निगरानी से जुड़े सिस्टम पर काम कर रही हैं। निजी कंपनियों के शामिल होने से यह क्षमता और मजबूत हो सकती है। अजिस्टा स्पेस का यह प्रयोग दिखाता है कि भारत अब सिर्फ लॉन्चिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में सक्रिय निगरानी और तकनीकी प्रदर्शन की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है।

अजब-गजब

नार्वे के इस शहर में मिट जाता है दिन और रात का फर्क

सर्वाइवल के लिए लोग लेते हैं विटामिन-डी की गोलियां और विशेष लाइट थेरेपी वाले लैंप्स का सहारा

निज संवाददाता : हम और आप अक्सर एक बादल छाने या एक दिन की बारिश होने से उदास हो जाते हैं, वहीं नॉर्वे के लॉन्गइयरबायेन में करीब 2,500 लोग हर साल लगातार चार महीने यानी नवंबर से फरवरी तक घने अंधेरे में ही अपनी जिंदगी बिताते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे पोलर नाइट कहते हैं। जहां सूरज पर्दे के पीछे ही रहता है और दुनिया पूरी तरह कृत्रिम रोशनी पर निर्भर हो जाती है। हमारी डेली रूटीन जहां सूरज की पहली किरण से तय होती है, वहीं यहां के लोगों की घड़ी नंबरों का खेल है। बाकी दुनिया में सूरज का उगना ताजगी लाता है, लेकिन यहां की सुबह और रात में कोई फर्क नहीं होता। यहां के लोग विटामिन-डी की गोलियां और विशेष लाइट थेरेपी वाले लैंप्स का सहारा लेते हैं। हमारे यहां संडे का मतलब पिकनिक होता है, लेकिन यहां संडे का मतलब है बर्फ के तूफान के बीच अपने घर के अंदर खुद को व्यस्त रखना। इतने लंबे अंधेरे में रहने वाले लोगों को चिड़चिड़ाहट और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। इससे लड़ने के लिए यहां के लोग एक फिलॉसफी अपनाते हैं, जिसे वे कोसेलिग कहते हैं। यह हमारी सुकून की भावना जैसा है। लोग अपने घरों को अनगिनत मोमबत्तियों, गर्म कॉफी और ऊनी कंबलों से सजाते हैं। अंधेरे को कोसने के बजाय यहां के लोग उसे त्यौहार की तरह मनाते हैं। हर शाम किसी न किसी के घर पर संगीत, बोर्ड गेम्स या कहानियों की महफिल सजती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां अकेलापन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका कम्युनिटी डिनर यानी सामूहिक भोज होता है। इस द्वीप पर करीब 50 अलग-अलग देशों के लोग रहते हैं, जो मुख्य रूप से रिसर्च या माइनिंग के लिए आए हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहां का आपसी जुड़ाव कमाल का है। अंधेरे के महीनों में यहां की सोशल लाइफ बाकी दुनिया से ज्यादा सक्रिय हो जाती है। लोग स्नोमोबाइल पर सवार होकर मीलों दूर नीली बर्फ की वादियों में नॉर्दर्न लाइट्स देखने निकलते हैं। हमारे लिए यह अजूबा है, उनके लिए रात की सैर है। यहां के लोग पोलर जैज जैसे म्यूजिक फेस्टिवल्स का आयोजन करते हैं ताकि शहर का सन्नाटा संगीत से भरा रहे। यहां के रूटीन सबसे रोचक है अंधेरे में सुरक्षा। जब आप अंधेरे में घर से निकलते हैं, तो आपको न केवल कड़ाके की ठंड मतलब माइनस 30 डिग्री तक की सर्दी से बचना है, बल्कि पोलर बीयर से भी सावधान रहना है। यहां इंसानों से ज्यादा भालू हैं और अंधेरे में वे और भी खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए यहां के लोग हमेशा अपनी हेडलाइट्स और रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनकर चलते हैं। यहां की सड़कों पर अजनबियों का एक-दूसरे को हेलो कहना आम है, क्योंकि इस घने अंधेरे में हर इंसान एक-दूसरे का सहारा होता है। सबसे रोचक बात यह है कि जब फरवरी के आखिर में पहली बार सूरज की किरण इस द्वीप के एक पुराने अस्पताल की सीढ़ियों पर पड़ती है, तो पूरा शहर वहां इकट्ठा होकर सोलफेस्टुका मनाता है। वह नजारा भावुक कर देने वाला होता है। लोग उस एक किरण को देखने के लिए हफ्तों इंतजार करते हैं। यह पल उन्हें याद दिलाता है कि अंधेरा कितना ही लंबा क्यों न हो, उजाला लौटकर जरूर आता है। स्वालबार्ड की यह काली रात हमें सिखाती है कि खुशियां बाहरी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होतीं। जहां हम छोटी-छोटी परेशानियों में घिर जाते हैं, वहां ये लोग 4 महीने के अंधेरे को एक-दूसरे के साथ, प्यार और उत्सव के साथ जीत लेते हैं।

मौत के आगोश में तीन बार पहुंची महिला ने सुनाया अनुभव

निज संवाददाता : अमेरिका के मैरीलैंड की रहने वाली 80 वर्षीय पादरी नॉर्मा एडवर्ड्स का दावा है कि वह अपने जीवन में तीन बार क्लीनिकली डेड घोषित की जा चुकी हैं और हर बार मौत के बाद उन्होंने एक अलग ही दुनिया का अनुभव किया। नॉर्मा बताती हैं कि उनका पहला सामना मौत से तब हुआ, जब वह महज 20 साल की थीं। काम पर जाते वक्त वह अचानक गिर पड़ीं और उनकी दिल की धड़कनें रुक गईं। डॉक्टरों ने बाद में बताया कि उनके शरीर में एक मृत भ्रूण मौजूद था, जिससे संक्रमण फैल गया था। नॉर्मा के अनुसार, जैसे ही वह बेहोश हुईं, उन्हें महसूस हुआ कि वह अपने शरीर से बाहर निकल गई हैं और ऑपरेशन टेबल पर पड़े खुद को ऊपर से देख रही हैं। उस वक्त उन्हें किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बाद वह तेज रफ्तार से एक अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ीं और अंत में एक बेहद चमकदार सफेद रोशनी में पहुंच गईं। इस रोशनी में नॉर्मा ने एक विशाल स्क्रीन देखी, जिस पर उनकी जिंदगी का पूरा लेखा-जोखा चल रहा था। उनके अनुसार, स्क्रीन पर तीन हिस्से थे पहले में वह जीवन था, जो धरती पर आने से पहले उनके लिए तय किया गया था। दूसरे में वह जिंदगी जो उन्होंने वास्तव में जी और तीसरे में उसका परिणाम। नॉर्मा का कहना है कि हर बार नतीजे में लिखा आता था कि उनका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इसी दौरान उनकी मृत चाची उनसे मिलीं, लेकिन उन्हें छूने से रोका और यह संदेश देकर वापस भेज दिया कि जीवन शाश्वत है और मौत अंत नहीं है। जब नॉर्मा वापस अपने शरीर में लौटीं, तो यह अनुभव उनके लिए बेहद पीड़ादायक था। वह इसे ऐसे समझाती हैं जैसे किसी विशाल आकाश को एक छोटे से पात्र में भरने की कोशिश की जा रही हो। इस घटना के बाद नॉर्मा का दावा है कि उनकी इंद्रियां पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील हो गईं और उन्हें असामान्य अनुभव होने लगे। नॉर्मा का कहना है कि नवंबर 2024 में उन्हें दो बार फिर कार्डियक अरेस्ट आया और वह एम्बुलेंस में ले जाते समय क्लीनिकली डेड घोषित की गईं। इस बार उनके अनुभव में एक महिला फरिश्ते ने उनका मार्गदर्शन किया और बताया गया कि उनका मिशन अभी अधूरा है।

खुदाई में मिले 6000 साल पुराने विशाल समुद्री शंख

निज संवाददाता : स्पेन के कैटेलोनिया क्षेत्र में की गई खुदाई के दौरान 6000 साल पुराने विशाल समुद्री शंख मिले हैं, जिनका इस्तेमाल उस दौर में लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। स्पेन के पुरातत्वविदों की इस खोज ने आधुनिक विज्ञान को भी हैरान कर दिया है। ये शंख केवल सजावटी वस्तुएं नहीं थे, बल्कि प्राचीन खेती करने वाले समुदायों की एक प्रभावशाली और संगठित संचार प्रणाली का अहम हिस्सा थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन शंखों से निकली आवाज आज भी इतनी तेज और स्पष्ट है कि वह पूरी घाटी में गूंज सकती है और जमीन के नीचे बनी गहरी खानों तक आसानी से पहुंच सकती है। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने इन प्राचीन शंखों को फिर से बजाकर उनकी ध्वनि क्षमता का परीक्षण किया। अध्ययन में सामने आया कि 'कैरोनिया लैम्पस' नामक बड़े समुद्री घोंघों के शंखों से बनाए गए ये हॉर्न 100 डेसीबल से भी ज्यादा तेज आवाज पैदा कर सकते हैं। पांच अलग-अलग पुरातात्विक स्थलों से मिले 12 शंखों में से आठ आज भी पूरी तरह काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी स्थिति में पाए गए एक शंख से 111.5 डेसीबल तक की आवाज दर्ज की गई, जो लगभग एक कार के हॉर्न के बराबर मानी जाती है। खुले मैदानों और पहाड़ी इलाकों में ऐसी आवाज को कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। ये शंख केवल एक ही तरह की जगहों से नहीं मिले हैं। वैज्ञानिकों को ये खेतों, गुफाओं और जमीन के नीचे बनी खानों में भी मिले हैं, जो लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे। इससे यह संकेत मिलता है कि यह किसी एक स्थान की सीमित परंपरा नहीं थी, बल्कि पूरे इलाके में अपनाई गई एक साझा सांस्कृतिक और व्यावहारिक प्रणाली थी। पहाड़ी और गुफाओं वाले क्षेत्रों में, जहां दूर तक देख पाना मुश्किल होता था, वहां ये शंख सूचना भेजने का सबसे भरोसेमंद माध्यम रहे होंगे। गहरी खानों में इनकी गूंज से सुरक्षा संकेत या चेतावनी देने का काम भी लिया जाता रहा होगा। शोध में यह भी सामने आया है कि प्राचीन कारीगरों ने इन शंखों को बेहद सोच-समझकर तैयार किया था। शंख के ऊपरी हिस्से को हटाकर लगभग 20 मिलीमीटर चौड़ा एक विशेष माउथपीस बनाया गया था, जिससे निकलने वाली आवाज स्थिर और नियंत्रित रहती थी। कुछ शंखों में छोटे छेद भी मिले हैं, जिनसे लगता है कि इन्हें डोरी के सहारे लटकाकर या साथ ले जाकर इस्तेमाल किया जाता था। इन पर समुद्री जीवों द्वारा किए गए प्राकृतिक छेद और निशान भी मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि इन्हें भोजन के लिए नहीं, बल्कि ध्वनि उत्पन्न करने के उद्देश्य से चुना गया था। परीक्षणों में यह भी स्पष्ट हुआ कि ये शंख केवल एक ही तरह की आवाज तक सीमित नहीं थे। कुछ शंखों से तीन अलग-अलग सुर निकाले जा सकते थे, जो संगीत की दृष्टि से सटीक और बार-बार दोहराए जा सकने योग्य थे। एक पेशेवर ट्रम्पेट वादक की मदद से इन शंखों की ध्वनिक क्षमता को मापा गया, जिससे यह साबित हुआ कि पाषाण काल के लोग केवल रस्मों तक सीमित नहीं थे, बल्कि व्यावहारिक जरूरतों के लिए भी अत्यंत उन्नत उपकरणों का उपयोग करते थे। हालांकि इस खोज के साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ा है। ईसा पूर्व 3600 के आसपास इस संचार तकनीक का इस्तेमाल अचानक बंद हो गया। कांस्य युग के बाद के स्तरों में इन शंखों के कोई प्रमाण नहीं मिलते।

धर्म

मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी है मौन व्रत

सनातन परंपरा में इसे माना जाता है सर्वोच्च तप

निज संवाददाता : सनातन परंपरा में मौन व्रत को सर्वोच्च तप माना गया है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का विशेष महत्व है, जो धार्मिक आस्था के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि यह पूरी चेतना और सजगता के साथ अपनाई जाने वाली एक आंतरिक साधना है। यह व्यक्ति को बाहरी अशांति से दूर कर अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। सदियों से आध्यात्मिक परंपराओं में मौन को आत्मबोध, आंतरिक स्वतंत्रता और सच्चे आनंद का मार्ग माना गया है। जब व्यक्ति मौन धारण करता है, तो उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती और मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। आयुर्वेद में भी मौन को मन की शांति, संयम और ऊर्जा संरक्षण से जोड़ा गया है। आयुर्वेद के अनुसार, अत्यधिक बोलना वात दोष को बढ़ाता है, जिससे बेचैनी, तनाव, अनिद्रा और मानसिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। मौन रहने से वात दोष संतुलित होता है, सत्व गुण में वृद्धि होती है और व्यक्ति अधिक स्थिर, संतुलित और जागरूक महसूस करता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, क्रोध पर नियंत्रण होता है और हृदय तथा ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं में भी सुधार देखा जाता है। भगवद्गीता में मौन को गुह्य ज्ञान कहा गया है और इसे मानसिक तप का स्वरूप माना गया है।गीता के अनुसार, वाणी पर संयम रखने से ओजस की रक्षा होती है, जिससे शरीर और मन दोनों सशक्त बनते हैं। मौन व्यक्ति को आत्मसंयम सिखाता है और आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। आधुनिक शोध भी मौन के लाभों की पुष्टि करते हैं। कई अध्ययनों में यह सामने आया है कि शोर प्रदूषण मानसिक तनाव को बढ़ाने के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। वहीं, नियमित रूप से मौन का अभ्यास करने से मस्तिष्क

पर सकारात्मक और उपचारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक शोध में पाया गया कि रोजाना कुछ समय मौन में बिताने से मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है, जिससे स्मरण शक्ति, सीखने की क्षमता और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। मौन तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है, हृदय गति और रक्तचाप को संतुलित रखता है, नींद की गुणवत्ता सुधारता है और रचनात्मकता को बढ़ाता है। यह ध्यान के समान प्रभाव डालता है और मस्तिष्क के लिए एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर मौन व्रत न केवल आध्यात्मिक साधना है, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। मालूम हो कि आज की तेज रफ्तार और शोर-शराबे से भरी जिंदगी में शांति मानो विलुप्त होती जा रही है। लगातार बढ़ती भागदौड़, तनाव और ध्वनि प्रदूषण ने न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, बल्कि मानसिक संतुलन भी बिगाड़ दिया है। ऐसे वातावरण में मौन का अभ्यास एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय बनकर सामने आता है।

भस्म चिकित्सा : आयुर्वेद की एक समृद्ध परंपरा

निज संवाददाता : आयुर्वेद में भस्म चिकित्सा की भी एक समृद्ध परंपरा रही है। इन्हीं भस्मों में शंख भस्म का विशेष स्थान है, जिसे आयुर्वेद में चमत्कारी औषधि माना जाता है। आयुर्वेद में रोगों के उपचार के लिए सदियों से जड़ी-बूटियों, खनिजों और भस्मों का प्रयोग किया जाता रहा है। रसशास्त्र में शंख को शुद्ध वर्ग के अंतर्गत खनिज रूप में वर्णित किया गया है और शंख भस्म को दैनिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में महत्वपूर्ण माना गया है। शंख भस्म का उपयोग मुख्य रूप से पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं के उपचार में किया जाता है। इसमें प्राकृतिक अम्लरोधी गुण पाए जाते हैं, जो एसिड रिफ्लक्स, सीने में जलन, खट्टी डकार और पेट दर्द जैसी समस्याओं में राहत देते हैं। कमजोर पाचन अग्नि के कारण गैस, उल्टी, सिरदर्द या भोजन न पचने की शिकायत होने पर शंख भस्म पाचन अग्नि को संतुलित करने का काम करती है। इससे भोजन का पाचन बेहतर होता है और पेट से जुड़ी परेशानियों में धीरे-धीरे सुधार आता है। शंख भस्म का सेवन बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए। इसे कभी भी सीधे नहीं खाया जाता, बल्कि शहद, घी, दही या चिकित्सक द्वारा बताई गई किसी अन्य सामग्री में मिलाकर ही सेवन किया जाता है। इसका स्वाद तीखा होता है और रोग की प्रकृति के अनुसार इसकी मात्रा तय की जाती है। बिना आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के इसका सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। शंख भस्म मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जो हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है। यह कैल्शियम की कमी को दूर करने, हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव में मदद करती है। दांतों की मजबूती बनाए रखने में भी शंख भस्म उपयोगी मानी जाती है। हालांकि गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार शंख भस्म शरीर में वात और कफ दोष को संतुलित करने का कार्य करती है। इन दोषों के असंतुलन से पेट, त्वचा और जोड़ों से जुड़ी कई बीमारियां जन्म लेती हैं। शंख भस्म के नियमित और नियंत्रित उपयोग से इन समस्याओं में राहत मिल सकती है।

लालबाजार कोर्ट लॉकअप में अब विचाराधीन कैदियों को भी मिलेगा गाय का गरम व शुद्ध दूध

कोलकाता पुलिस की नई पहल

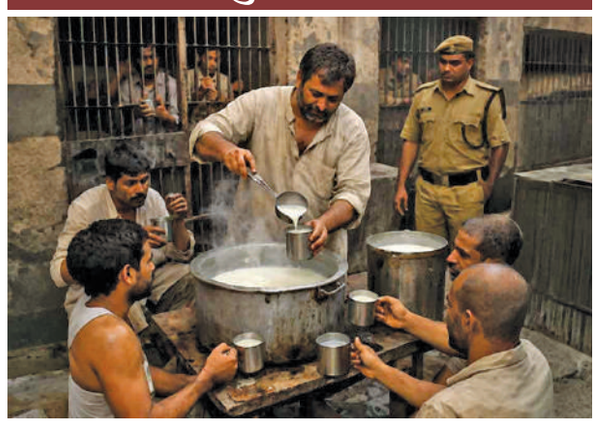

निज संवाददाता : चावल में कंकड़ का एक भी दाना नहीं होना चाहिए। दूध गाय का और शुद्ध होना चाहिए। इसे शुद्ध सरसों के तेल में पकाया जाना चाहिए। लालबाजार में कोर्ट लॉकअप में अंडरट्रायल कैदियों के लिए नया मेन्यू लाया जा रहा है। कोर्ट लॉकअप में आने के बाद भी कैटरिंग में कोई कमी न हो, मेहमानों को गरम शुद्ध गाय का दूध दिया जाए। कोलकाता पुलिस ने अब ऐसा इंतज़ाम किया है कि जेल से कोर्ट लाए जाने के बाद कैदियों को चार दिनों तक खाने की दिक्कत न हो। कोलकाता पुलिस का रिज़र्व फ़ोर्स डिवीज़न न सिर्फ़ सही मात्रा में खाना, बल्कि खाने की क्वालिटी भी अच्छी हो, इस पर सख़्त है। लालबाजार के सूत्रों ने बताया कि शुरुआत में यह मेन्यू सिटी सेशंस एंड फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और एसीएमएम (2) कोर्ट लॉकअप के कैदियों के लिए तैयार किया जा रहा है। धीरे-धीरे शहर के दूसरे कोर्ट लॉकअप के कैदियों के लिए भी मेन्यू तैयार करने और अच्छा खाना देने का प्लान है। जेल से कोर्ट लाए जाने वाले हर कैदी के लिए दिन और रात के खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। इसमें नाश्ता और शाम का खाना भी होगा। पुलिस ने बताया कि फर्स्ट क्लास कैदियों को दिन हो या रात, ज़रूरत पड़ने पर दोनों टाइम चावल, रोटी, दाल, करी, मछली का शोरबा दिया जाएगा। जो लोग मछली नहीं खाते, उनके लिए मौसमी फल होंगे। सेकंड क्लास कैदियों के लिए रोज़ाना के मेन्यू में चावल, रोटी, दाल, करी, मछली का शोरबा होगा। ऐसे में, जो कैदी मछली नहीं खाता, उसे दूध या दही दिया जाएगा। दोनों क्लास के कैदियों के लिए नाश्ते का मेन्यू चाय और रोटी है। उन्हें दोपहर या शाम को चाय और दो बिस्किट दिए जाएंगे। कोलकाता पुलिस ने हर कैदी के लिए खाने की मात्रा भी तय कर दी है।

जैसे

* चावल 248 ग्राम
* आटा 247 ग्राम
* दाल 145 ग्राम
* सब्ज़ियां 200 ग्राम
* आलू 58 ग्राम
* वेल्ली गुड़ 14.5 ग्राम।
* मछली की मात्रा भी 14.5 ग्राम रखी गई है। ऐसे में उन्हें हर दिन 29 ग्राम मछली दी जा सकती है। पुलिस ने खाना देने वालों को निर्देश दिया है कि फर्स्ट क्लास कैदियों को महंगा बढ़िया चावल देना होगा। सेकंड क्लास कैदियों के लिए चावल की क्वालिटी मीडियम होगी। लेकिन उसमें कंकड़ या गंदगी नहीं होगी। करी को ताज़ी सब्ज़ियों के साथ पकाना होगा। कैदियों को रुई, कतला या मृगल के अलावा कोई और मछली नहीं दी जाएगी। जो कैदी दूध पीते हैं उन्हें गाय का दूध देना होगा। वह दूध शुद्ध होना चाहिए। उसे शुद्ध सरसों के तेल में पकाना होगा। खाना पकाने में नमक और मसाले काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल होने चाहिए। खाना पकाने से पहले दालों को चुनकर साफ़ कर लेना चाहिए। खाना पकाना अच्छा होना चाहिए। कैदियों को गरम खाना दिया जाना चाहिए। बीमार कैदियों के मामले में उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार खाना दिया जाना चाहिए। लालबाज़ार ने कहा कि आम तौर पर कोर्ट लॉकअप में हर कैदी के लिए खाने का आवंटन 2 रुपए 73 पैसे है। अब से हर कैदी के लिए खाने का आवंटन 73 रुपए 50 पैसे कर दिया गया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आम तौर पर, कोर्ट में पेश होने से पहले अंडरट्रायल कैदियों को जेल में ही खाना खाना पड़ता है। फिर उन्हें कैदी वैन में कोर्ट लाया जाता है। लेकिन अब उन्हें वहां चाय और दो रोटियां या बिस्कुट दिए जाते हैं। इस बीच, जिन कैदियों को सुबह-सुबह ट्रायल के लिए कोर्ट लॉकअप में ले जाया जाता है, वे खतरे में रहते हैं। कुछ मामलों में, कैदी के परिवार वाले पुलिस से घर से खाना लाने की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन देखा गया है कि कोर्ट आने वाले कई अंडरट्रायल कैदियों को दिन भर बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता। उन्हें रात में खाने के लिए वापस जेल जाना पड़ता है। फिर से, घर के खाने के मामले में अक्सर सुरक्षा मे जोखिम होते हैं।

राज्यपाल बोस ने किया 'वंदे भारत अवार्ड' का ऐलान

निज संवाददाता : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी. वी. आनंद बोस ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून को वंदे भारत अवार्ड देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत का ज्ञान दुनिया से बेहतर ज्ञान है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा पद्धति पर विचार व्यक्त किए। राज्यपाल डॉ. बोस ने कहा कि भारत का ज्ञान विश्व के ज्ञान से व्यापक और समृद्ध है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत की शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। हमारी सभ्यता अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रही है, जिसे नई पीढ़ी तक प्रभावी रूप से पहुंचाना समय की मांग है। उन्होंने सम्मेलन के विषय की सराहना करते हुए कहा कि एएमयू द्वारा चुना गया विषय अत्यंत प्रासंगिक और सार्थक है।

विकास, विश्वास और भविष्य की नई उड़ान

तन्मय जैन

भोपाल : मध्यप्रदेश में 18 फरवरी को पेश होने वाला बजट 2026-27 प्रदेश के विकास इतिहास में एक सकारात्मक और परिवर्तनकारी अध्याय जोड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह बजट ''विकसित मध्यप्रदेश'' के विजन को साकार करने की दिशा में ठोस और प्रभावी कदम साबित होगा। सरकार के संकेतों से स्पष्ट है कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि आमजन के सपनों को साकार करने की व्यापक कार्ययोजना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए इसे तैयार किया गया है।

कृषि और ग्रामीण समृद्धि की नई शुरुआत

कृषि प्रधान राज्य होने के कारण इस बार बजट में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने जा रही है। आधुनिक सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, फसल बीमा योजनाओं का सुदृढ़ क्रियान्वयन और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही ग्रामीण सड़कों, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क के विस्तार से किसानों को बेहतर बाजार सुविधा उपलब्ध होगी।

युवाओं के सपनों को पंख

बजट 2026-27 युवाओं के लिए अवसरों का द्वार खोलने वाला साबित होगा। कौशल विकास केंद्रों की संख्या में वृद्धि, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, आईटी पार्क और तकनीकी संस्थानों के विस्तार जैसी घोषणाएँ प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुख बनाने में सहायक होंगी। डिजिटल शिक्षा और नवाचार आधारित योजनाएँ मध्यप्रदेश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करेंगी।

स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। जिला अस्पतालों के उन्नयन, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से आम नागरिकों को बेहतर उपचार मिलेगा। मातृ-शिशु स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त संसाधन समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाएंगे।

अधोसंरचना और निवेश का सशक्त आधार

सड़क, एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक कॉरिडोर और शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए बड़े प्रावधान राज्य को औद्योगिक दृष्टि से और मजबूत करेंगे। निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीतियां और नई परियोजनाएं प्रदेश में रोजगार सृजन को गति देंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का स्पष्ट लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश को निवेश और उद्योग के लिए सबसे आकर्षक राज्य बनाया जाए।

महिला सशक्तिकरण को नई ऊर्जा

महिलाओं के स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहयोग, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार बजट की प्रमुख विशेषता होगी। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि होगी।

विकास का विश्वास

18 फरवरी को पेश होने वाला यह बजट मध्यप्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह बजट प्रदेश को आर्थिक मजबूती, सामाजिक समता और सतत विकास की दिशा में नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाला सिद्ध होगा। निस्संदेह, मध्यप्रदेश बजट 2026-27 विकास और विश्वास की वह नई उड़ान है, जो प्रदेश के हर नागरिक के चेहरे पर आशा और आत्मविश्वास की मुस्कान लाने का संकल्प लेकर आ रहा है।

टी-20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

♦ पहली बार मैच का हिस्सा बनेंगे ये 15 खिलाड़ी

निज संवाददाता : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक मुकाबला 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है। यह हाई-वोल्टेज क्लैश कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें ग्रुप ए के एक अहम मैच में भिड़ेंगी। इस मुकाबले के जीतने वाली टीम सुपर-8 में अपनी जगह भी पक्की कर ली। यह मैच खास इसलिए है क्योंकि भारतीय टीम लंबे समय बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज सीनियर खिलाड़ियों के बिना आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान से भिड़ रही है। अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में नई पीढ़ी मैदान पर इस राइवेलरी को आगे बढ़ाएगी। दूसरी ओर, पाकिस्तान भी एक युवा टीम के साथ सलमान अली आगा की कप्तानी में खेलने उतरेगी। दोनों टीमों के कुल 15 खिलाड़ी पहली बार टी वर्ल्ड कप के मंच पर इस ऐतिहासिक राइवेलरी का हिस्सा बनेंगे। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन और कुलदीप यादव ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कभी भी टी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेला है। ये सभी युवा और स्टार क्रिकेटर इस बड़े मैच में डेब्यू जैसा अनुभव लेंगे। वहीं, पाकिस्तान की ओर से भी कई नए चेहरे इस मुकाबले में पहली बार भारत से भिड़ेंगे। साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, ख्वाजा नफे, सलमान आगा, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक इस लिस्ट में शामिल हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा के पास भी टी वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने का कोई अनुभव नहीं है। कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ यह पहला बड़ा मुकाबला उनके लिए ज्यादा दबाव पैदा कर सकता है। बाकी आईसीसी इवेंट की तरह टी वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का दबदबा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच टी-20 वर्ल्ड कप में अभी तक कुल 8 मुकाबले खेल गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम ने 7 बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। वहीं, पाकिस्तान की टीम 1 बार ही बाजी मार सकी है। पिछली बार भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान का हराया था। वहीं, हाल ही में एशिया कप के दौरान भी पाकिस्तान को लगातार 3 मैचों में भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

मनोरंजन

लैला-मजनू के रूहानी इश्क से लेकर हीर-रांझा की पाक मोहब्बत

कागा सब तन खाइयो, चुन-चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस'

निज संवाददाता : सूफी संत बाबा फरीद की इन पक्तियों में उन प्रेमियों की तड़प शामिल है, जो मिलकर भी कभी मिल ना सके। इनकी पाक मोहब्बत की राह में दुनिया ही दुश्मन बनकर खड़ी रही। सदियों से ऐसे दीवानों की कहानी हमारी लोककथाओं का भी हिस्सा रही हैं। लैला-मजनू से लेकर हीर-रांझा तक अपनी मोहब्बत की वजह से ही अमर हो गए। इन प्रेमियों की, आशिकों की दर्द भरी प्रेम कहानियों को बड़े पर्दे पर हिंदी सिनेमा ने भी बखूबी उतारा है। जानते हैं इन प्यार में डूबे जोड़ों की कहानी को कैसे-कैसे और कब हिंदी फिल्मों में दिखाया गया। रांझा रांझा करते-करते हीर दीवानी हुई प्यार का जिक्र हो और हीर-रांझा की बात ना ऐसा कैसे हो सकता है। 16वीं शताब्दी में पंजाब प्रांत में यह प्रेम कहानी पनपी। दोनों के बीच प्यार हुआ लेकिन परिवार और दुनिया ही दुश्मन बन बैठी। हीर की शादी जबरन कराई जाने लगी। लेकिन हीर ने जहर खा लिया। हीर की मौत रांझा को बर्दाश्त ना हुई, उसने भी मौत को गले लगाया। इस दर्द भरी कहानी को हिंदी सिनेमा में कई बार दिखाया गया। साल 1970 में चेतन आनंद निर्देशित फिल्म 'हीर रांझा' में राज कुमार और प्रिया राजवंश पर यह प्रेम कहानी फिल्माई गई। फिल्म में हीर से दूर होकर रांझा का दिल दर्द से भर उठता है। इस दर्द को एक गाने 'ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं' में बखूबी बयां किया जाता है। इसी तरह हीर भी अपना दुख बयां करती है, जिस पर फिल्म में गीत है, 'दो दिल टूटे दो दिल हारे दुनिया वालों सदके तुम्हारे।' यह फिल्म, गीत आज भी दर्शकों की जुबान पर हैं और हीर-रांझा का प्यार भी प्रेमियों के मन में जिंदा है। इसी तरह साल 1992 में 'हीर रांझा' नाम से एक फिल्म बनी, जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी ने मुख्य भूमिका अदा की। पंजाबी भाषा में भी इसी नाम से कई फिल्में बनी। इन्हें दर्शकों ने खूब सराहा।

सोहनी ने चेनाब किनारे पुकारा महिवाल का नाम

18वीं सदी में पंजाब में ही फली-फूली थी सोहनी और महिवाल की प्रेम कहानी। कुम्हार की बेटी सोहनी के प्यार में व्यापारी का बेटा महिवाल चरवाहा बन गया। दोनों को बेइंतहा मोहब्बत हुई लेकिन समाज को, परिवार को इनका प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ। सोहनी ने महिवाल को पाने की खातिर चेनाब नदी को पार करने की हिमाकत की लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। सोहनी डूब गई, महिवाल भी नदी में कूद पड़ा। इस प्रेम का कहानी का अंत भी दर्दनाक हुआ। इस प्यार, दर्द को बॉलीवुड ने बड़े शिद्दत से बड़े पर्दे पर उतारा। 'सोहनी महिवाल' नाम से कई बालीवुड फिल्में बनीं। साल 1933 और 1946 में दो हिंदी फिल्में बनीं लेकिन साल 1958 में रिलीज हुई 'सोहनी महिवाल' सबसे चर्चित रही। इसमें भारत भूषण और निम्मी ने मुख्य भूमिका कीं। वहीं साल 1984 में सनी देओल और पूनम ढिल्लों अभिनीत फिल्म 'सोहनी महिवाल' को भी खूब प्यार मिला। सनी देओल स्टारर फिल्म के कई गानों में सोहनी और महिवाल के रूहानी इश्क की दास्तां को बयां किया गया। फिल्म का एक गाना 'लोगों ने सर पे लगाए हैं हजारों इल्जाम आजा, सोहनी चेनाब दे किनारे से पुकारे तेरा नाम आजा।' यह गाना सोहनी और महिवाल की मजबूरी और इश्क में कुछ भी कर गुजरने की चाहत को बखूबी जता देता है।

मजनू की मोहब्बत में सजा पाने को हाजिर हुआ लैला का इश्क

'हुस्न हाजिर है मोहब्बत में सजा पाने को' जब यह गाना ऋषि कपूर और रंजीता कौर अभिनीत फिल्म 'लैला मजनू (1976)' में सुनाई देता है, तब इस गाने को सुनकर दर्शकों के जेहन में 11वीं सदी की अरब देश की अधूरी प्रेम कहानी की यादें ताजा हो जाती हैं। इसी नाम से साल 1953 में नूतन और शम्मी कपूर ने भी एक फिल्म की। वहीं साल 2018 में इम्तियाज अली की लिखी कहानी पर बनी 'लैला मजनू' भी एक कल्ट मूवी बन चुकी है। इन सभी फिल्मों में लैला से मिलने की चाहत लिए भटकता मजनू आखिरी में मौत के आगोश में सो जाता है।

साहिबान की मोहब्बत में टूटा मिर्जा का दिल

हीर और रांझा, सोनी महिवाल की तरह ही साहिबान और मिर्जा की कहानी भी पंजाब में 16वी शताब्दी में पनपी थी। साहिबान को मिर्जा से बेइंतहा मोहब्बत थी वह कभी उससे बेवफाई नहीं कर सकती थी लेकिन वक्त आने पर वफा भी नहीं कर पाई। उसने मिर्जा के तीर तोड़ दिए, जिससे वह उसके भाइयों को ना मारे। लेकिन साहिबान के भाइयों ने मिर्जा को मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर साहिबान ने भी मौत को चुन लिया और अपने मिर्जा के साथ ही दुनिया से रूखसत हो गई। इसी कहानी को साल 2016 में फिल्म 'मिर्जियां' में नए जमाने के हिसाब से दिखाया गया, फिल्म को ओमप्रकाश मेहरा ने निर्देशित किया था। इसी तरह एक पंजाबी फिल्म 2012 में भी इसी प्रेम कहानी पर बनी, जिसमें ग्रिप्पी ग्रेवाल मिर्जा के रोल में दिखे।

जूलियट की मोहब्बत में कुर्बान हुआ रोमियो

मशहूर ब्रिटिश राइटर शेक्सपियर ने कई बड़े नॉवेल लिखे। लेकिन 'रोमियो और जूलियट' उनका सबसे फेमस नॉवेल है। इस पर कई फिल्में हॉलीवुड में बनी हैं। वहीं बॉलीवुड की कई फिल्में इस नॉवेल से इंस्पायर रहीं। इसमें साल 2013 की 'राम लीला' भी है, रणवीर और दीपिका की इस फिल्म का दर्दनाक अंत होता है। राम लीला मौत के बाद ही मिल पाते हैं क्योंकि समाज और परिवार की दीवारें उन्हें इस जहान में मिलने नहीं देती हैं। वहीं 'कयामत से कयामत तक (1988)', 'एक-दूजे के लिए (1981)' और 'सनम तेरी कसम (1982)' जैसी कई फिल्में भी रोमियो और जूलियट की कहानी से ही इंस्पायर रही हैं।

जटिलताओं से भरी है भारतीय राजनीति : सनी लियोनी

निज संवाददाता : हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने अपने जीवन, करियर और भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चुनौतियों पर खुलकर बात की। एक बातचीत में सनी से पूछा गया कि हॉलीवुड में एक्टर्स अक्सर पॉलिटिकल मुद्दों पर बेबाक होकर अपनी राय रखते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कम देखने को मिलता है। इस पर सनी ने बिश के युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुख बनाने में सहायक होंगीो बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। उन्होंने कहा-भारत में कई तरह के समूह हैं। आपको कभी नहीं पता चलता कि आपकी कौन-सी बात किसे बुरी लग जाए। बात को पकड़कर उसे ट्विस्ट कर देना यहां बहुत आसान है। सनी के मुताबिक, यही कारण है कि कई भारतीय सेलिब्रिटीज पॉलिटिक्स पर चुप रहना ही ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी शब्द को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है, इसलिए पब्लिक फिगर्स अक्सर राजनीतिक विवादों से दूरी बनाए रखते हैं। हालांकि, सनी लियोनी का यह भी मानना है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण जैसे विषय स्वच्छ हवा, पेड़-पौधों की जरूरत और शहरों की सफाई पर बेझिझक बात की जा सकती है क्योंकि ये चीजें आम लोगों से सीधे जुड़ी हैं और किसी राजनीतिक झगड़े का हिस्सा नहीं बनतीं। सनी ने बताया कि उनके पति डेनियल वेबर इन सामाजिक मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं। वह बीएमसी को ट्वीट करके अपने इलाके की समस्याएं बताते रहते हैं, और कई बार उनकी शिकायतों पर कार्रवाई भी होती है। सनी के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स पर बोलने के बाद आने वाले परिणाम झेलने के लिए तैयार है, तो वह जरूर इस पर चर्चा कर सकता है, लेकिन ज्यादातर कलाकार ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहते।

कोलकाता के मंच से अरिजीत सिंह ने की स्टेज पर धमाकेदार वापसी

निज संवाददाता : प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान करने के कुछ ही दिनों बाद बॉलीवुड के लोकप्रिय सिंगर अरिजीत सिंह ने स्टेज पर धमाकेदार वापसी की। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बीते रविवार रात को उन्होंने सितार वादक अनुष्का शंकर के साथ परफॉर्म किया। अनुष्का शंकर के चैप्टर्स टूर 2026 का यह इवेंट हिस्सा था, जिसमें अरिजीत गेस्ट परफॉर्मर के तौर पर शामिल हुए। जैसे ही उन्हें स्टेज पर बुलाया गया, पूरा स्टेडियम तालियों और चीयरिंग से गूंज उठा। स्टेज पर आते ही अरिजीत ने दर्शकों से कहा-मैं बहुत नर्वस हूं, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। उनकी यह सादगी भरी बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इस मौके पर अरिजीत और अनुष्का ने तबला वादक बिक्रम घोष के साथ मिलकर बांग्ला रचना माया भोरा राती पेश की, जिसे लक्ष्मी शंकर ने गाया था और पंडित रवि शंकर ने इसका संगीत तैयार किया था। क्लासिकल और समकालीन संगीत का यह संगम दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। इसके बाद दोनों ने ट्रेसेस ऑफ यू का ड्यूएट वर्जन प्रस्तुत किया, जो मूल रूप से अनुष्का और नोरा जोन्स का गाना है। लगभग 20 मिनट की यह परफॉर्मेंस दर्शकों ने खूब सराही और सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो गए। अरिजीत ने परफॉर्मेंस के बाद बताया कि हाल ही में वह अनुष्का के घर गए थे और दोनों ने मिलकर एक नई धुन पर काम किया। इस खुलासे ने फैंस में उत्सुकता बढ़ा दी कि भविष्य में दोनों की कोई खास पेशकश सुनने को मिल सकती है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई, जहां फैंस भावुक होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। गौरतलब है कि 27 जनवरी को अरिजीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की थी कि वह अब प्लेबैक सिंगिंग के नए असाइनमेंट नहीं लेंगे। उन्होंने अपने करियर को शानदार बताते हुए श्रोताओं का आभार जताया और बाद में ट्वीट में स्पष्ट किया कि यह फैसला लंबे सोच-विचार के बाद लिया गया है। हालांकि, स्टेज पर उनकी यह वापसी साबित कर देती है कि उनकी आवाज़ और कला आज भी फैंस के दिलों में उतनी ही जीवंत है।

स्वामी मोहता पब्लिशिंग हाउस के लिए, प्रकाशक, मुद्रक : अजय कुमार मोहता द्वारा अरिहंत मुद्रा, 61, सूर्यसेन स्ट्रीट, कोलकाता-700009 से मुद्रित एवं प्रकाशित। **संपादकीय कार्यालय :** 10, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरणी, (क्लाइब रो), 5बी मंजिल, रूम नं. 9, कोलकाता-700001, **स्थानीय कार्यालय :** 28-5 कन्वेंट रोड, मौलाली, कोलकाता-700014। **संपादक : अजय कुमार मोहता,** मो. 9830045693, E-mail-gambheersamachar@gmail.com. Website. www.gambheersamachar.in (प्रकाशित रचनाओं के चयन, संपादन हेतु पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी, सभी कानूनी विवाद के लिए कोलकाता न्याय क्षेत्र)